वर्ष 12 • अंक 301 • 18 पृष्ठ
• मूल्य 5 रुपये

बुधवार 5 फरवरी 2020

कोलकाता, चंडीगढ़, **नई दिल्ली**, पटना, भोपाल, मुंबई, रायपुर और लखनऊ से प्रकाशित।

भारत का पहला संपूर्ण हिंदी आर्थिक अखबार

बिज़नेस स्टैंडर्ड

www.bshindi.com

▸▸ पृष्ठ 4

बिजली क्षेत्र का कम कोयला आवंटन का आरोप

भास्कर भट्ट ▸▸ पृष्ठ 3

भट्ट को 25 करोड़ रुपये का विशेष सेवानिवृत्ति लाभ

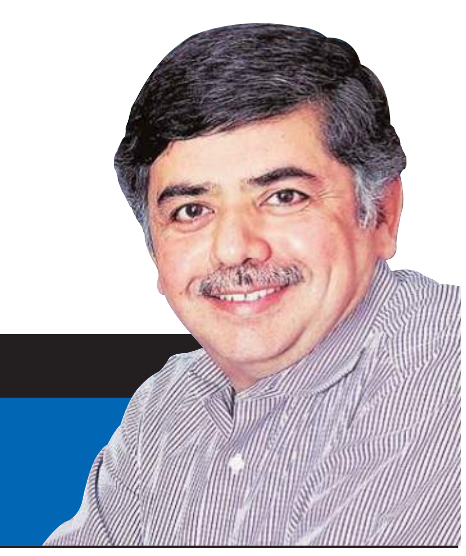

डॉलर रु. 71.30 ▼ 10 पैसे | यूरो रु. 78.80 ▼ 20 पैसे | सोना (10ग्राम) ₹ 40443 ▼ 211 रुपये | सेंसेक्स 40789.40 ▲ 917.10 | निफ्टी 11979.70 ▲ 271.80 | निफ्टी फ्यूचर्स 11964.30 ▼ 15.40 | ब्रेंट क्रूड 53.90 डॉलर ▲ 0.70 डॉलर

एक नज़र

10 सरकारी बैंकों के विलय पर मुहर आज!

केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के 10 बैंकों को मिलाकर चार बैंक बनाने की योजना पर बुधवार को मुहर लगा सकती है। आधिकारिक सूत्र ने बताया कि बुधवार को होने वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह प्रस्ताव पारित हो सकता है। इस योजना में 10 सार्वजनिक बैंकों का पुनर्गठन चार बैंकों में किया जाना है। इनके बहीखातों के विलय की प्रक्रिया 1 अप्रैल तक पूरी कर ली जाएगी। सभी बैंकों के बोर्ड में अदला-बदली अनुपात को मंजूरी के लिए रखा जाएगा। इस योजना में बैंक कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों को सुरक्षित रखने के प्रावधान भी होंगे। यह सार्वजनिक बैंकों के विलय की सबसे बड़ी कवायद होगी। पृष्ठ 4

भारती एयरटेल को 1,035 करोड़ रुपये का घाटा

भारती एयरटेल को चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 1,035 करोड़ रुपये का एकीकृत शुद्ध घाटा हुआ। इससे पूर्व वित्त वर्ष 2018-19 की इसी तिमाही में कंपनी को 86 करोड़ रुपये का लाभ हुआ था। हालांकि दिसंबर 2019 को समाप्त तिमाही में कंपनी की आय 8.5 फीसदी बढ़कर 21,947 करोड़ रुपये रही जो एक साल पहले इसी तिमाही में 20,231 करोड़ रुपये थी। पृष्ठ 2

पीएनबी को 492 करोड़ रुपये का घाटा

पंजाब नैशनल बैंक (पीएनबी) को चालू वित्त वर्ष की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में एकल आधार पर 492.28 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हुआ है। फंसे कर्ज के एवज में प्रावधान बढ़ने से बैंक को घाटा हुआ है। एक साल पहले इसी तिमाही में बैंक को 246.51 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था। सितंबर 2019 तिमाही में बैंक को 507.05 करोड़ रुपये का लाभ हुआ था। पीएनबी ने कहा कि बैंक दसंबर, 2019 तिमाही में बैंक की कुल आय 15,967.49 करोड़ रुपये रही जबकि एक साल पहले इसी तिमाही में उसकी आय 14,854.24 करोड़ रुपये थी। पृष्ठ 2

जीएसटी बिल लेने वालों की खुलेगी लॉटरी

ग्राहकों को सामान खरीदने पर बिल लेने के लिए प्रोत्साहित करने के वास्ते सरकार एक लॉटरी योजना लाने जा रही है। इस वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लॉटरी योजना के तहत 10 लाख रुपये से एक करोड़ रुपये तक का इनाम दिया जाएगा। जो ग्राहक खरीदारी का बिल लेंगे, वे ही लॉटरी जीत सकेंगे। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के सदस्य जॉन जोसफ ने कहा कि जीएसटी के प्रत्येक बिल पर ग्राहक को लॉटरी जीतने का मौका मिलेगा। इससे ग्राहक कर चुकाने को प्रोत्साहित होंगे। सीबीडीटी के चेयरमैन पीसी मोदी ने कहा कि करदाता के पास विकल्प होगा कि नई और पुरानी कराधान व्यवस्था में अदला-बदली कर सकते हैं। पृष्ठ 4

एयर इंडिया में 100 फीसदी एफडीआई की तैयारी

सरकार राष्ट्रीय विमानन कंपनी एयर इंडिया में जोरशोर के साथ विनिवेश की तैयारी में लगी है। ऐसे में सरकार एयर इंडिया में 100 फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति देने के प्रस्ताव पर काम कर रही है। अभी सरकारी मंजूरी मार्ग से एयर इंडिया में 49 फीसदी विदेशी निवेश की अनुमति है। अनुसूचित विमान कंपनियों में कुछ शर्तों के साथ 100 फीसदी एफडीआई की अनुमति है। इनमें एक शर्त यह भी है कि विदेशी विमानन कंपनी को इसकी अनुमति नहीं होगी।

व्यापार गोष्ठी

आम बजट पर आपकी राय?

अपनी राय पासपोर्ट साइज फोटो और पूरे पते के साथ हमें इस पते पर भेजें :

बिज़नेस स्टैंडर्ड, नेहरू हाउस, 4 बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002 फैक्स नंबर - 011-23720201
या फिर ई-मेल करें goshthi@bsmail.in
अपने विचार आप हमें bshindi.com पर भी भेज सकते हैं

आज का सवाल

क्या वित्त मंत्री की अपील पर निवेश करने आगे आएंगे उद्योगपति

www.bshindi.com पर राय भेजें।
आप अपना जवाब एसएमएस भी कर सकते हैं। यदि आपका जवाब हां है तो **BSP Y** और यदि न है तो **BSP N** लिखकर **57007** पर भेजें।

पिछले सवाल का नतीजा

वैश्विक बॉन्ड सूचकांक में प्रतिभूतियों को शामिल करने से मिलेगा लाभ?

हां	55.56%
नहीं	44.44%

बाजार ने पाटा बजट का घाटा

तेल में गिरावट और वैश्विक बाजारों में तेजी से सेंसेक्स और निफ्टी 2.3 फीसदी चढ़े

सुंदर सेतुरामन
मुंबई, 4 फरवरी

तेल की कीमतों में गिरावट और वैश्विक बाजारों में तेजी का असर आज घरेलू बाजार में भी दिखा। इस बीच आम बजट के दिन से बाजार में आई गिरावट की भी भरपाई हो गई।

सेंसेक्स 917 अंक चढ़कर 40,790 पर बंद हुआ, वहीं निफ्टी 272 अंक की तेजी के साथ 11,980 पर बंद हुआ। दोनासें सूचकांकों में सितंबर के बाद एक दिन में यह सबसे बड़ी तेजी रही। शनिवार को बजट के दिन सेंसेक्स में तेज गिरावट दर्ज की गई थी और 39,735 के स्तर पर बंद हुआ था।

बाजार के भागीदारों का कहना है कि निवेशकों ने इस उम्मीद में खरीदारी की कि कच्चे तेल के दाम में नरमी से बृहद आर्थिक हालात में स्थिरता आएगी। इसके साथ ही चीन के बाजार में बिकवाली थमने से भी निवेशकों की धारणा को बल मिला।

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने 366 करोड़ रुपये की शुद्ध लिवाली की। कोरोनावायरस के फैलने की खबर से पिछले एक हफ्तों से विदेशी निवेशकों की ओर से बिकवाली की जा रही थी। घरेलू संस्थागत निवेशकों ने लगातार दूसरे दिन लिवाली की। आज उन्होंने 600 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे।

किसे हुआ फायदा, कौन नुकसान में

इनमें तेजी	बंद भाव	वृद्धि (फीसदी में)
टाइटन कंपनी	1,275.5	7.6
आईटीसी	215.7	3.9
एचडीएफसी	2,345.7	3.8
बजाज फाइनैंस	4,518.1	3.6
टाटा स्टील	452.1	3.6
पावर ग्रिड	194.3	3.5
हीरो मोटोकॉर्प	2,462.3	3.4
इन्हें नुकसान	**बंद भाव**	**गिरावट (फीसदी में)**
बजाज ऑटो	3,162.5	3.9
हिंदुस्तान यूनिलीवर	2,155.0	1.1

*बंद भाव 4 फरवरी को रुपये में

विशेषज्ञों ने कहा कि वैश्विक हालात में सुधार के साथ ही बजट में कुछ प्रोत्साहनों की घोषणा से विदेशी निवेशकों की धारणा में सुधार हुआ है।

पिछले कुछ दिनों में तेज गिरावट के बाद ब्रेंट क्रूड एक साल के निचले स्तर 53.72 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है। तेल की कीमतों में गिरावट से भारत को लाभ होता है क्योंकि यह सबसे बड़ा तेल आयातक है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि कच्चे तेल के दाम में प्रति 10 डॉलर की वृद्धि से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति 0.4 फीसदी बढ़ जाती है।

चीन में नरमी की चिंता के बीच तेल के दाम में कमी आई है। वैश्विक कच्चे तेल की 14 फीसदी की आपूर्ति चीन को की जाती है। अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि वायरस की वजह से अगली कुछ तिमाहियों में चीन की अर्थव्यवस्था में नरमी बनी रह सकती है। सोमवार को चीन के बाजार में निवेशकों को हुए करीब 700 अरब डॉलर के नुकसान के बाद चीन के केंद्रीय बैंक ने रिवर्स बॉन्ड खरीद करार के तहत 173.81 अरब डॉलर डालने का निर्णय किया है।

वेलेंटिस एडवाइजर्स के संस्थापक ज्योतिवर्द्धन जयपुरिया ने कहा, 'भारतीय बाजार वैश्विक बाजारों से काफी हद तक जुड़ा हुआ है और आय की तेजी चीन द्वारा नकदी बढ़ाने के प्रयासों का ही हिस्सा है। आगे अर्थव्यवस्था में सुधार किस तरह का रहता है, बाजार उस पर निर्भर करेगा।' विनिर्माण क्षेत्र के अच्छे आंकड़ों से भी निवेशकों का मनोबल बढ़ा है। विनिर्माण पीएमआई जनवरी में आठ साल के उच्च स्तर 55.3 रहा।

कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि बाजार में तेजी संभवतः शॉर्ट कवरिंग की वजह से आई हो और निवेशकों को सतर्क रहने की जरूरत है। मार्केसेलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के संस्थापक सौरभ मुखर्जी ने कहा, 'भारतीय अर्थव्यवस्था उन कंपनियों के पक्ष में है जिनके पास नकदी का प्रवाह ज्यादा है। बैंकिंग और एनबीएफसी हमारी कंपनियों के विकास के लिए कर्ज देने की स्थिति में नहीं हैं। शेयर बाजार में इन्हीं बड़ी कंपनियों में लिवाली ज्यादा है।'

कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सूचकांक में 3.5 फीसदी और धातु सूचकांक में 3.3 फीसदी की तेजी आई। सेंसेक्स कंपनियों में सबसे ज्यादा 7.5 फीसदी की तेजी टाइटन में देखी गई। आईटीसी और एचडीएफसी के शेयर भी अच्छी बढ़त पर बंद हुए।

नए नियमों से विदेशी लाभांश पर असर!

सचिन मामबटा और अदिति दिवेकर
मुंबई, 4 फरवरी

- **विदेशी इकाइयों से मिले लाभांश पर लगता है 15 फीसदी कर**
- **इस राशि पर नहीं लगता है लाभांश वितरण कर**
- **नई व्यवस्था में लाभांश पाने वाले पर लगेगा कर**
- **विदेशी इकाइयों से मिले लाभांश पर अब लगेगा दोहरा कराधान**

लाभांश कराधान नियमों में संशोधन से घरेलू कंपनियों को विदेशी सहायक कंपनियों से मिला लाभांश प्रभावित हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि पहले लागू कराधान के नियमों में बदलाव से विदेशी सहायक कंपनियों से मिली और मूल कंपनियों द्वारा अपने शेयरधारकों को वितरित राशि पर दोहरा कराधान लग सकता है।

ईवाई इंडिया में इंटरनैशनल टैक्स ऐंड ट्रांजेक्शन सर्विसेज के नैशनल लीडर प्रणव सत्या ने कहा कि भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशी इकाइयों से मिले लाभांश पर 15 फीसदी की दर से रियायती कर लगता है। जब मूल कंपनी अपने शेयरधारकों को लाभांश वितरण करती है तो इस राशि पर लाभांश वितरण कर नहीं लगता है। इस तरह समान आय पर दोहरा कराधान नहीं लगता है।

मान लीजिए कि किसी मूल कंपनी को अपनी विदेशी इकाई से 70 रुपये मिलते हैं और वह अपने शेयरधारकों को 100 रुपये लाभांश देती है। वित्त वर्ष 2020 में केवल 30 रुपये की राशि पर 20.56 फीसदी की दर से लाभांश वितरण कर लगेगा। केवल उन शेयरधारकों को 10 फीसदी अतिरिक्त कर देना होगा जिनका सालाना लाभांश 10 लाख रुपये से अधिक होगा। सत्या ने कहा, 'लेकिन अब यह सब गया।'

नए नियमों के तहत मूल कंपनी के शेयरधारकों पर पूरे 100 रुपये के लाभांश पर कर लगेगा। अगर कुछ शेयरधारक उच्चतम कर श्रेणी में आते हैं तो उन्हें 42.7 फीसदी कर देना होगा। इसमें लाभांश पर दो बार कर लगाया जाएगा।

टैक्स कंसल्टेंसी फर्म प्राइसवाटरहाउसकूपर्स में पार्टनर (टैक्स ऐंड रेग्युलेटरी सर्विसेज) तुषार सचाड़े ने भी कहा कि विदेशी इकाई से मिले लाभांश पर 15 फीसदी कर लगता था। अलबत्ता, अगर मूल कंपनी लाभांश का भुगतान करती थी तो उसे विदेशी लाभांश पर लाभांश वितरण कर नहीं देना होता था।

उन्होंने कहा, 'अब विदेशी इकाई के मामले में दोहरा कराधान है। अगर भारतीय मूल कंपनी को लाभांश मिलता है तो उसे कर देना होगा। जब वह लाभांश देने की घोषणा करेगी तो इसे पाने वाले को भी कर चुकाना होगा।'

भारतीय कंपनियों ने कई विदेशी कंपनियों का अधिग्रहण किया है। उदाहरण के लिए आदित्य बिड़ला समूह की धातु क्षेत्र की दिग्गज कंपनी हिंडाल्को इंडस्ट्रीज ने 2007 में नोवेलिस का अधिग्रहण किया था। इसी तरह टाटा स्टील ने ब्रिटेन की कंपनी कोरस ग्रुप का 2007 में अधिग्रहण किया था। इन कंपनियों से मिले किसी भी लाभांश पर उच्च कर चुकाना पड़ सकता है। हालांकि भारत के बाहर कई देशों में टाटा स्टील का कारोबार लाभांश देने की स्थिति में नहीं है। एक सूत्र ने बताया कि हिंडाल्को को भी फिलहाल विदेश से लाभांश मिलने की उम्मीद नहीं है।

झिझक छोड़ निवेश को आगे आए उद्योग जगत

शुभायन चक्रवर्ती
नई दिल्ली, 4 फरवरी

निर्मला सीतारमण
केंद्रीय वित्त मंत्री

- **वित्त मंत्री ने उद्योगपतियों से की अर्थव्यवस्था में निवेश की अपील**
- **उद्योग के हित में उठाए गए कदमों की दी जानकारी**
- **वित्त मंत्री ने कहा कि आलोचक सवाल उठा रहे हैं कि कॉरपोरेट कर में कटौती के बाद भी निवेश नहीं आ रहा है**

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतीय उद्योग जगत को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि वह झिझक को दरकिनार कर नरम पड़ती अर्थव्यवस्था के विकास को बढ़ावा देने के लिए निवेश करे। उन्होंने कहा कि सरकार ने कारोबार के हित में कॉरपोरेट कर में कटौती, न्यूनतम वैकल्पिक कर खत्म कररने और कंपनियों से लाभांश वितरण कर (डीडीटी) का बोझ हटाने जैसे कई उपाय किए हैं।

भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) द्वारा बजट बाद आयोजित चर्चा में वित्त मंत्री ने कहा, 'हम जितना कर सकते हैं, उतना किया। हम उद्योग के रास्ते को आसान बनाने के लिए आगे भी काम करने को तैयार हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज यह स्थिति है कि केवल सरकार के खर्च से आर्थिक वृद्धि में तेजी आ सकती है। अब मैं उम्मीद करती हूं कि अर्थव्यवस्था की गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए आप भी बराबर के इंजन बनें।'

उन्होंने उद्योग के अगुआ को अर्थव्यवस्था में निवेश के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहा कि आलोचक कहते हैं कि सरकार ने कॉरपोरेट कर की दरें घटा दीं लेकिन निवेश कहां है? दर में कटौती किए छह महीने हो गए हैं।' सीतारमण ने कहा, 'मैं इससे बहुत खुश हूं। कम से कम बैंकों को पैसा मिल रहा है। अगर आप लाभांश दे रहे हैं तो यह अच्छा है क्योंकि पैसा शेयरधारकों के पास वापस जा रहा है। अगर आप डॉलर बचा रहे हैं तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इस बचत का कहीं न कहीं सदुपयोग होगा।'

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार के फैसले के बाद कंपनियों को जो पैसा मिला है, उसे कहां लगाना है, इसका फैसला कंपनियों को ही करना है। उन्होंने सीआईआई के सदस्यों से कहा, 'सरकार और उद्योग, हर किसी को अर्थव्यवस्था की मदद करनी होगी। सभी को विकास का इंजन बनना होगा। आपमें उद्यमिता की भावना है और हम इसमें आपकी मदद करने वाले हैं।'

उन्होंने कहा कि करदाताओं को रियायत के बिना कम कर दरों का विकल्प देने के उनके प्रस्ताव का मकसद कम कर दरों के साथ आसान व्यवस्था बनाना है। डीडीटी सहित सभी करों में भी यह देखने को मिलेगा।

आम बजट 2020-21 पर भारतीय उद्योग जगत ने मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है। उद्योग के एक धड़े का मानना है कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए साहसिक सुधारों की जरूरत थी लेकिन बजट में ठोस उपाय नहीं किए गए। दूसरी ओर कुछ उद्योगपतियों का मानना है कि वित्त मंत्री के पास ज्यादा गुंजाइश नहीं थी।

आप की वैट माफी योजना, 24 घंटे बाजार खोलने का वादा

बीएस संवाददाता
नई दिल्ली, 4 फरवरी

- **प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों में 24 घंटे दुकानें खोलने, छापेमारी व सीलिंग से मुक्ति का वादा**
- **सफाईकर्मियों की मृत्यु पर 1 करोड़ रुपये मुआवजा, संविदाकर्मियों को स्थायी करने का वादा**

आम आदमी पार्टी (आप) ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आज जारी घोषणापत्र में कारोबारियों के पुराने वैट मामले निपटाने के लिए माफी योजना लाने और प्रमुख व्यासायिक क्षेत्रों में प्रयोग के तौ पर 24 घंटे बाजार खोलने का वादा किया है। इसके अलावा कारोबारियों को छापेमारी से राहत जारी रखने, सीलिंग से सुरक्षा, बाजार व औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए पर्याप्त धन आवंटित करने, महिलाओं को अपने घरों से या आसपास नौकरी व व्यवसाय के अवसर देने के साथ ही सर्किल दर को युक्तिसंगत बनाने और 6 महीने के भीतर रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को वेंडिंग प्रमाण पत्र के जारी करने का भी वादा किया है।

आप के घोषणापत्र में सफाईकर्मियों को काम के दौरान मृत्यु होने पर 1 करोड़ रुपये मुआवजा, नए सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति, संविदाकर्मियों को स्थायी करने, विश्वस्तरीय सड़कें, स्कूलों में देशभक्ति पाठ्यक्रम, यमुना रिवर साइड का विकास, घर तक राशन की आपूर्ति, 10 लाख बुजुर्गों को तीर्थयात्रा, अनधिकृत कॉलोनियों में विकास कार्य, किसानों के हक में भूमि सुधार अधिनियम में संशोधन व फसल नुकसान पर 50 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजा जारी रखने के साथ ही दिल्ली को पूर्ण राज्य दर्जा दिलाने, जनलोकपाल व स्वराज अधिनियम को लागू करने के लिए केंद्र पर दबाव डालने का वादा शामिल है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणापत्र जारी करते हुए कहा कि पांच साल बुनियादी मुद्दे ठीक करने में बीते अब दिल्ली को 21वीं सदी का आधुनिक शहर बनाना है।

ऑटो एक्सपो में 100 नए मॉडल से उठेगा पर्दा

शैली सेठ मोहिले
नई दिल्ली, 4 फरवरी

- **इस बार कई कंपनियों ने किया किनारा**
- **पिछली बार उतारे गए थे 80 नए मॉडल**
- **मोबिलिटी सॉल्यूशंस पर रहेगा जोर**
- **फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी मिलाया हाथ**

दिल्ली के करीब ग्रेटर नोएडा में बुधवार से शुरू हो रहे ऑटो एक्सपो-मोटर शो 2020 में इस बार 90 से 100 नए मॉडल पर से पर्दा उठेगा। छह दिन तक चलने वाली यह प्रदर्शनी वैश्विक मोटर शो कैलेंडर का एक प्रमुख आयोजन है। इसका आयोजन ऐसे वक्त हो रहा है जब भारतीय अर्थव्यवस्था दशक के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है।

बाजार की खस्ता हालत और कमजोर धारणा के बावजूद इस साल पिछली बार से ज्यादा नए मॉडल उतारे जाएंगे। सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरर्स सायम, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन और उद्योग संस्था सीआईआई द्वारा आयोजित पिछले संस्करण में कुल 80 नए मॉडलों पर से पर्दा उठाया गया था। इस बार अधिकांश दोपहिया वाहनों, कार और वाणिज्यिक वाहन बनाने वाली कई कंपनियों ने इस प्रदर्शनी से किनारा कर लिया है। इसके बावजूद इसमें पिछली बार से अधिक नए मॉडल उतारे जाएंगे।

चीन में कोरोनावायरस फैलने की वजह से चीन की वाहन कंपनियों के अधिकारी भारत नहीं आ पाएंगे लेकिन भारत में उनके अधिकारियों की एक्सपो में मौजूदगी रहेगी। पहली बार इस शो में हिस्सा ले रही कंपनियां 30 नए उत्पाद और कॉन्सेप्ट का प्रदर्शन करेंगी। इनमें किया मोटर्स इंडिया, एमजी मोटर इंडिया, ग्रेट वॉल मोटर्स, ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक और एफएडब्ल्यू हायमा जैसी कार निर्माता कंपनियां शामिल हैं।

एक्सपीरियल के संस्थापक अभीक चट्टोपाध्याय कहते हैं कि इस साल के शो की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें उत्पादों का ही नहीं बल्कि प्रौद्योगिकी का भी प्रदर्शन हो रहा है। इसकी व्यापक थीम मोबिलिटी सॉल्यूशंस है। यात्री वाहन बनाने वाली कई कंपनियों ने अपने मंडप को इस थीम के मुताबिक ढाला है। इनमें टाटा मोटर्स, महिंद्रा, मारुति सूजुकी और हुंडई मोटर इंडिया शामिल है।

इसमें हिस्सा लेने वाली कंपनियों की सूची में पहली बार टेलीकॉम ब्रांड भी शामिल है। रिलायंस की कंपनी जियो इस शो में अपने कनेक्टेड मोबिलिटी सॉल्यूशन का प्रदर्शन करेगी। वाहनों की खरीद के फैसले में सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए ऑटो एक्सपो ने फेसबुक के साथ हाथ मिलाया है। एक्सपो में नए वाहनों और प्रौद्योगिकी के लॉन्च के वीडियो और लाइव शो का फेसबुक और इंस्टाग्राम पर प्रसारण किया जाएगा। इस तरह लोग मोबाइल के जरिये ऑटो एक्सपो में हो रही गतिविधियों से जुड़े रहेंगे।

खबरों में रहे स्टॉक

बजाज ऑटो

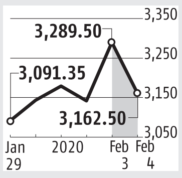

जनवरी में दोपहिया बिक्री 22 फीसदी घटकर 1,57,796 वाहन रही

₹ 3,289.50 पिछला बंद भाव
₹ 3,162.50 आज का बंद भाव
▼ 3.86 %

ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन

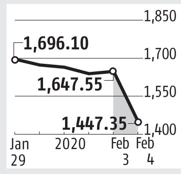

तीसरी तिमाही में शुद्ध नुकसान 661 करोड़ रुपये रहा

₹ 1,647.55 पिछला बंद भाव
₹ 1,447.35 आज का बंद भाव
▼ 12.15 %

हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया

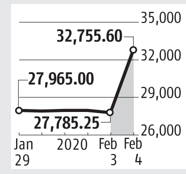

तीसरी तिमाही में कर पूर्व लाभ 47 फीसदी उछलकर 194 करोड़ रुपये रहा

₹ 27,785.25 पिछला बंद भाव
₹ 32,755.60 आज का बंद भाव
▲ 17.89 %

आईआरसीटीसी

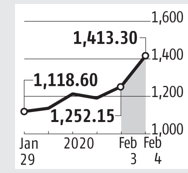

सूचीबद्धता कीमत 644 रुपये के मुकाबले अब दोगुने से ज्यादा हुआ

₹ 1,252.15 पिछला बंद भाव
₹ 1,413.30 आज का बंद भाव
▲ 12.87 %

श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनैंस

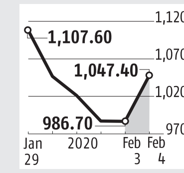

तीसरी तिमाही में शुद्ध लाभ 38 फीसदी बढ़कर 879 करोड़ रुपये रहा

₹ 986.70 पिछला बंद भाव
₹ 1,047.40 आज का बंद भाव
▲ 6.15 %

संक्षेप में

अदाणी ट्रांसमिशन ने 31 करोड़ डॉलर जुटाए

भारत में निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन कंपनी अदाणी ट्रांसमिशन लिमिटेड (एटीएल) ने विदेशी मुद्रा में कर्ज के तौर पर 31 करोड़ डॉलर की रकम जुटाई है। कंपनी ने एक बयान में कहा है, 'डॉलर पर आधारित यह पूंजी एटीएल की 6 पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों द्वारा जुटाई गई है।' *एजेंसियां*

इलेक्ट्रोस्टील स्टील्स संग वीएसएल का विलय मंजूर

वेदांत लिमिटेड ने मंगलवार को कहा कि राष्ट्रीय कंपनी विधि पंचाट (एनसीएलटी) के कोलकाता पीठ ने उसकी इकाई वेदांत स्टार का इलेक्ट्रोस्टील स्टील्स लिमिटेड (ईएसएल) के साथ विलय की योजना को मंजूरी दे दी है। *एजेंसियां*

भारती एयरटेल को 1,035 करोड़ रुपये का घाटा

बीएस संवाददाता/एजेंसियां
नई दिल्ली/मुंबई, 4 फरवरी

कंपनी परिणाम

भारती एयरटेल को चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में शुद्ध रूप से 1,035 करोड़ रुपये का एकीकृत घाटा हुआ। हालांकि, इससे पूर्व वित्त वर्ष 2018-19 की इसी तिमाही में कंपनी को 86 करोड़ रुपये का लाभ हुआ था। बयान में कहा गया है कि इस दौरान कंपनी की आय में वृद्धि हुई है। दिसंबर 2019 को समाप्त तिमाही में कंपनी की आय 8.5 फीसदी बढ़कर 21,947 करोड़ रुपये रही, जो एक साल पहले इसी तिमाही में 20,231 करोड़ रुपये थी।

भारती एयरटेल के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्याधिकारी (सीईओ) गोपाल विट्टल ने एक बयान में कहा, उद्योग की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए दिसंबर 2019 में शुल्क दरों में संशोधन स्वागत योग्य कदम है, लेकिन हमारा मानना है कि आने वाले समय में शुल्क में और बढ़ोतरी होनी चाहिए ताकि उद्योग उभरती प्रौद्योगिकी में निवेश करने में सक्षम हो। आलोच्य अवधि में भारती एयरटेल इंडिया का राजस्व एक साल पहले की तीसरी तिमाही के मुकाबले 7 फीसदी बढ़कर 15,797 करोड़ रुपये हो गया। दिसंबर तिमाही में एयरटेल का एकीकृत राजस्व 8.5 फीसदी बढ़कर 21,947 करोड़ रुपये रहा। इससे पहले वर्ष की दूसरी तिमाही में भारती एयरटेल ने अब तक का सबसे बड़ा 23,045 करोड़ रुपये का घाटा दर्ज किया था। कंपनी द्वारा 28,450 करोड़ रुपये उच्चतम न्यायालय के फैसले के तहत सांविधिक बकाया के लिए रखे जाने से यह घाटा हुआ। सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले साल एजीआर के मामले में सरकार के रुख को सही ठहराया था। भारती एयरटेल की देनदारी में 35,586 करोड़ रुपये जुड़ गए हैं, जिसमें लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम यूजेज शुल्क का बकाया शामिल है। कंपनी का शेयर आज बीएसई पर 1.72 फीसदी बढ़कर 519.10 रुपये पर बंद हुआ। कंपनी ने बाजार बंद होने के बाद नतीजे घोषित किए। कंपनी का औसत राजस्व प्रति ग्राहक दिसंबर में सुधरकर 135 रुपये पर पहुंच गया, जो पिछली तिमाही में 128 रुपये रहा था।

पीएनबी को 492 करोड़ रुपये का नुकसान

सोमेश झा
नई दिल्ली, 4 फरवरी

पंजाब नैशनल बैंक वित्त वर्ष 2019-20 की तीसरी तिमाही में घाटे में चली गई और इस तरह से दो सरकारी बैंकों के साथ नियोजित विलय से पहले बैंक ने पहला तिमाही नुकसान दर्ज किया।

दिसंबर 2019 की तिमाही में पीएनबी का शुद्ध नुकसान 492.3 करोड़ रुपये रहा जबकि पिछले साल की समान अवधि में बैंक ने 507 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया था। फंसे कर्ज के लिए प्रावधान 73 फीसदी बढ़कर 4,445 करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जो पिछले साल की समान अवधि में 2,565 करोड़ रुपये रहा था। प्रावधान में भारी उछाल से दूसरे सबसे बड़े सार्वजनिक बैंक का लाभ प्रभावित हुआ।

पिछली बार 2018-19 की सितंबर तिमाही में पीएनबी ने नुकसान दर्ज किया था और तब उसका शुद्ध नुकसान 453 करोड़ रुपये रहा था। इस वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में बैंक की शुद्ध ब्याज आय एक साल पहले की समान अवधि के मुकाबले 4,355 करोड़ रुपये पर स्थिर रही। दिसंबर तिमाही में फंस कर्ज में शामिल होने वाली उधारी पिछले साल की समान अवधि के 3,324 करोड़ रुपये के मुकाबले 6,783 करोड़ रुपये पर पहुंच गई। फंसे कर्ज में ज्यादातर उधारी कृषि (2,100 करोड़ रुपये), एमएसएमई (1,400 करोड़ रुपये) क्षेत्र की शामिल हुई। बैंक ने हाउसिंग फाइनैंस कंपनी डीएचएफएल के लिए 1,189 करोड़ रुपये का प्रावधान किया। वोडाफोन आइडिया को दी गई 1,000 करोड़ रुपये की उधारी बैंक का दबाव बढ़ाएगी। बैंक को अगली दो तिमाहियों में एनपीए में 3,000 करोड़ रुपये शामिल होने का अंदेशा है।

जेएसडब्ल्यू एनर्जी के लाभ में मामूली बढ़त

निजी क्षेत्र की बिजली उत्पादक जेएसडब्ल्यू एनर्जी का कर पूर्व लाभ विशिष्ट आय के कारण दिसंबर तिमाही में मामूली बढ़ोतरी के साथ 212.65 करोड़ रुपये रहा। बिजली की कम मांग के चलते कंपनी के राजस्व व बिजली उत्पादन को झटका लगा।

दिसंबर 2019 की तिमाही में कंपनी का कर पूर्व लाभ मामूली बढ़ोतरी के साथ 212.65 करोड़ रुपये रहा। कंपनी के लाभ में 61.46 करोड़ रुपये की विशिष्ट आय शामिल है। कंपनी का शुद्ध लाभ एकीकृत स्तर पर 404.31 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल की समान अवधि के 147.08 करोड़ रुपये के मुकाबले दोगुने से ज्यादा है। मौजूदा व टली हुई कर देनदारी के कारण कंपनी के शुद्ध लाभ को सहारा मिला।

तिमाही में कंपनी का राजस्व सालाना आधार पर 19 फीसदी घटकर 2,016 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल की समान अवधि में 2,492 करोड़ रुपये रहा था। कंपनी ने कहा, अल्पावधि में कम बिक्री और ईंधन लागत में गिरावट के कारण राजस्व घटा। कंपनी के संयुक्त प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्याधिकारी प्रशांत जैन ने कहा, बिजली की मांग के लिहाज से यह तिमाही कमजोर रही। हालांकि 22 जनवरी के बाद बिजली की मांग 1.7 फीसदी बढ़ी। दिसंबर तिमाही में शुद्ध बिजली उत्पादन 458 करोड़ यूनिट रहा, जो एक साल पहले 511.6 करोड़ यूनिट रहा था। कंपनी की अल्पावधि में बिक्री घटकर 54.1 करोड़ यूनिट रही, जो पहले 111.2 करोड़ यूनिट रही थी।

जीएमआर एनर्जी की सहायक जीएमआर कलिंगनगर सौदे पर प्रबंधन ने कहा कि वह अगले कुछ हफ्ते में इस सौदे के लिए करार पर हस्ताक्षर करेंगे।

सीएसबी बैंक का कर पूर्व लाभ कई गुना बढ़ा

फेयरफैक्स समर्थित सीएसबी बैंक का कर पूर्व लाभ दिसंबर तिमाही में कई गुना बढ़कर 42.4 करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जो पिछले साल की समान अवधि में 1.6 करोड़ रुपये रहा था। बैंक का शुद्ध लाभ इस अवधि में पिछले साल की समान अवधि के 0.7 करोड़ रुपये से बढ़कर 28.1 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। बैंक की शुद्ध ब्याज आय 31 फीसदी की उछाल के साथ 155.2 करोड़ रुपये पर पहुंच गई, जो पिछले साल की समान अवधि में 118.3 करोड़ रुपये रही थी।

बैंक का शुद्ध एनपीए पिछले साल के 3.7 फीसदी से घटकर 2 फीसदी रह गया। इस तरह से शुद्ध एनपीए दिसंबर तिमाही में पिछले साल की समान अवधि के 365.5 करोड़ रुपये के मुकाबले घटकर 213.7 करोड़ रुपये रह गया। बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 15.5 फीसदी के मुकाबले बढ़कर 23 फीसदी पर पहुंच गया। दिसंबर में प्रावधान कवरेज अनुपात एक साल पहले के 66.2 फीसदी के मुकाबले बढ़कर 80.3 फीसदी पर पहुंच गया।

पीरामल एंटरप्राइजेज का लाभ बढ़ा

पीरामल एंटरप्राइजेज लिमिटेड (पीईएल) का कर पूर्व लाभ दिसंबर 2019 में समाप्त तीसरी तिमाही में 6.6 फीसदी की उछाल के साथ 954 करोड़ रुपये पर पहुंच गया।

वाणिज्यिक वाहन बिक्री में सुधार की उम्मीद

टी ई नरसिम्हन
चेन्नई, 4 फरवरी

बजट से वाणिज्यिक वाहन (सीवी) बिक्री में सुधार आएगा। अर्थव्यवस्था पर दबाव बरकरार रहने की वजह से यह बिक्री कमजोर बनी हुई है। उद्योग के प्रतिनिधियों का कहना है कि ट्रांसपोर्टरों के पास अधिशेष क्षमता की वजह से एमएचसीवी बिक्री कमजोर बनी रहने की आशंका है।

देश की सबसे बड़ी सीवी निर्माता टाटा मोटर्स की घरेलू बाजार में वाणिज्यिक वाहन बिक्री जनवरी 2020 में 15 प्रतिशत तक घटकर 31,348 वाहन रही जो एक साल पहले 37,089 वाहन थी। बिक्री को एमऐंडएचसीवी खंड की वजह से दबाव का सामना करना पड़ा। एमऐंडएचसीवी की बिक्री एक साल पहले के 11,694 वाहनों की तुलना में 41 प्रतिशत घटकर 6,914 वाहन रह गई। चालू वित्त वर्ष के दौरान कुल घरेलू सीवी बिक्री एक साल पहले के 378,664 से 26 प्रतिशत तक घटकर 279,947 वाहन रह गई। एमऐंडएचसीवी बिक्री एक साल पहले के 12,22,41 की तुलना में 46 प्रतिशत घटकर 67,145 रह गई।

टाटा मोटर्स में कमर्शियल व्हीकल्स बिजनेस यूनिट के अध्यक्ष गिरीश वाघ ने कहा कि खुदरा बिक्री लगातार सातवें महीने थोक बिक्री से आगे रही है जिससे स्टॉक घटाने में मदद मिली है, क्योंकि हम बीएस-6 क्रियान्वयन के नजदीक हैं। खासकर वाहन मालिकों के बीच खरीदारी दिलचस्पी बढ़ने से जनवरी 2020 में एमऐंडएचसीवी बिक्री पिछले सात महीनों में दूसरी सर्वाधिक रही। छोटे वाणिज्यिक वाहनों में, खरीदारी रुझान अन्य सेगमेंट्स की तुलना में बेहतर बना हुआ है जिसके परिणामस्वरूप इसमें 2 प्रतिशत की सालाना वृद्धि दर्ज की गई है।

> बजट में कृषि और इन्फ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिए जाने से मूल उपकरण निर्माताओं को बजट से कुछ राहत मिलने की उम्मीद दिख रही है

अशोक लीलैंड के एमऐंडएचसीवी की घरेलू बिक्री जनवरी 2020 में 49 प्रतिशत घटकर 6,949 वाहन रह गई जो एक साल पहले 13,663 थी। जहां एमऐंडएचसीवी ट्रकों की बिक्री समान महीने के दौरान 60 प्रतिशत तक घटी, वहीं बसों की बिक्री में 30 प्रतिशत तक का इजाफा दर्ज किया गया। घरेलू बाजार में एमऐंडएचसीवी ट्रकों की बिक्री 4,837 वाहन दर्ज की गई जो जो पिछले 12,042 वाहनों के आंकड़े की तुलना में 60 प्रतिशत की गिरावट हे। बस बिक्री 1,621 से बढ़कर 2,112 पर रही। हल्के वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री 4,870 की तुलना में 20 प्रतिशत घटकर 3,901 वाहन पर रही।

जनवरी में घरेलू बाजार में कुल वाहन बिक्री 18,533 से 41 प्रतिशत तक घटकर 10,850 वाहन रही।

अशोक लीलैंड के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्याधिकारी विपिन सोंधी ने कहा कि कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास के लिए 2.83 लाख करोड़ रुपये के आवंटन से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मदद मिलेगी और इसका दीर्घावधि में सीवी उद्योग पर सकारात्मक असर दिखेगा। अगले पांच साल के दौरान 100 लाख करोड़ रुपये के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा दिए जाने से वाणिज्यिक वाहन क्षेत्र के लिए सकारात्मक बदलाव आएगा।

उन्होंने कहा कि आर्थिक गतिविधि में तेजी आने और रोजगार पैदा होने से वस्तु एवं खपत में मांग बढ़ेगी और ट्रकों के लिए ढुलाई गतिविधि के अवसर भी बढ़ेंगे।

अशोक लीलेंड के मुख्य परिचालन अधिकारी अनुज कथूरिया ने हाल में कहा कि एमऐंडएचसीवी उद्योग वित्त वर्ष 2019-20 का समापन लगाग 2,00,000 वाहनों की बिक्री के साथ करेगा, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 46.23 प्रतिशत की गिरावट है।

2019-20 में उद्योग की कुल बिक्री लगभग 2,00,00 वाहन रहेगी जो पिछले साल 3,72,000 वाहन थी।

इंडियन होटल्स करेगी बड़ा विस्तार

टाटा के स्वामित्व वाली इंडियन होटल्स कंपनी हर महीने एक होटल खोलेगी

पवन लाल
मुंबई, 4 फरवरी

मैरियट समूह से मुकाबला

- हर महीने कम से कम एक होटल खोलने से कंपनी की इन्वेंट्री में इस साल कम से कम **2,500** कमरे जुड़ जाएंगे
- कंपनी के प्रबंध निदेशक और सीईओ पुनीत चटवाल ने कहा, वित्त वर्ष के नौ महीने में हमने नौ होटल खोले
- यह कदम अपनी इन्वेंट्री को साल **2022** तक **25,000** पर पहुंचाने के रणनीतिक लक्ष्य का हिस्सा है, जिसमें से **7,000** विकास के चरण में हैं

टाटा के स्वामित्व वाली होटल शृंखला इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड (आईएचसीएल) हर महीने कम से कम एक होटल खोलने के लिहाज से पटरी पर है, जिसके जरिये कंपनी की इन्वेंट्री में इस साल कम से कम 2,500 कमरे जुड़ जाएंगे, जो उसे बढ़त के अप्रत्याशित चरण की ओर ले जाएगा।

हालांकि बाजार की अग्रणी मैरियट ग्रुप ने भी विस्तार की आक्रामक योजना तैयार की है। पिछले साल मैरियट ने भारत में 13 होटल खोले, जो मैरियट, कंट्रीयार्ड बाय मैरियट, फेयरफील्ड बाय मैट्रियट, द रिट्ज कार्लटन, द फोर प्वाइंट्स, द ली मेरिडियन और शेरेटन जैसे ब्रांड के तहत खुले हैं। इस साल बहुराष्ट्रीय कंपनी ने एक दर्जन और होटल खोलने की योजना बनाई है और मैरियट के अधिकारियों का कहना है कि 2020 के आखिर तक कमरों की संख्या 25,000 से बढ़कर 28,000 पर पहुंचने की संभावना है।

आईएचसीएल के प्रबंध निदेशक और सीईओ पुनीत चटवाल ने कहा, वित्त वर्ष के नौ महीने में हमने नौ होटल खोले। उन्होंने स्पष्ट किया, यह कदम अपनी इन्वेंट्री को साल 2022 तक 25,000 पर पहुंचाने के रणनीतिक लक्ष्य का हिस्सा है, जिसमें से 7,000 विकास के चरण में हैं। अभी ताज के 18,500 कमरे हैं।

नए होटलों में ताज फतेह प्रकाश पैलेस उदयपुर, देवी रतन जयपुर और ताज कन्वेंशन सेंटर गोवा जैसे होटल शामिल होंगे। गोवा में नया होटल खुलने के बाद आईएचसीएल की वहां होटल की संख्या 11 हो जाएगी और कंपनी वहां सबसे बड़ी ऑपरेटरों में से एक बन जाएगी। इस साल आईएचसीएल के अन्य होटल दार्जिलिंग, शिलॉन्ग, गंगटोक, वायनाड, हरिद्वार, नवी मुंबई, भरूच, कराड और कलिंगनगर में खुलेंगे। निकट भविष्य में कंपनी के नए होटलों में जिंजर की हिस्सेदारी कम से कम एक चौथाई होगी। पिछले दो साल में आईएचसीएल ने चार अलग-अलग ब्रांडों के तहत 46 होटलों के लिए करार पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें विवांता, जिंजर और सेलक्यूशंस शामिल हैं। पहले जिन के लिए अनुबंध हुआ है, अब वे खुल रहे हैं।

एक विश्लेषक ने कहा, पर्यटन के नए केंद्र उभर रहे हैं, जो बड़े ऑपरेटरों का ध्यान खींच रहे हैं और भविष्य के लिए अहम यह है कि ऐसी जगहों पर कितनी तेजी से हॉस्पिटैलिटी की व्यवस्था वहां तैयार होती है। उदाहरण के लिए, आईएचसीएल उन इलाकों पर भी नजर डाल रही है जहां पहले होटल नहीं खोले गए हैं। कंपनी ने गंगटोक में दो, सिक्किम व तवांग (अरुणाचल प्रदेश) में एक-एक होटल के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। मैरियट भी रणनीतिक ठिकानों पर होटल खोल रही है जिनमें सिलिगुड़ी, सूरत और कोलकाता शामिल है। साथ ही त्रिवेंद्रम, नवी मुंबई और महाबलेश्वर के लिए भविष्य की योजना बनी है। विश्लेषकों ने कहा, पर्यटन उद्योग में किसी कंपनी के लिए आकार व वॉल्यूम से ज्यादा अहम लाभ में बने रहना होता है। उस मानक पर आईएचसीएल पटरी पर है। चटवाल ने कहा, हालांकि अभी मंदी है, लेकिन हमने पुनर्गठन आदि के जरिये अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं, लागत को उपयुक्त बना रहे हैं और गैर-प्रमुख परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण कर रहे हैं। इस वजह से लगातार सात तिमाही तक हमने मार्जिन में बढ़ोतरी दर्ज की है। तीसरी तिमाही में आईएचसीएल का कर पश्चात लाभ 26 फीसदी बढ़कर 203 करोड़ रुपये रहा जबकि एबिटा मार्जिन 32.7 फीसदी, जो एक दशक का सर्वोच्च स्तर है।

लाभांश वितरण कर की समाप्ति सही कदम : अजय त्यागी

सुंदर सेतुरामन
मुंबई, 4 फरवरी

बाजार नियामक सेबी ने लाभांश पर कर देनदारी का भार कंपनियों से शेयरधारकों पर डालने के सरकार के कदम का स्वागत किया है। नैशनल स्टॉक एक्सचेंज के एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद संवाददाताओं से बातचीत में सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी ने कहा, लाभांश वितरण कर की समाप्ति की मांग बाजार कर रहा था। लाभांश वितरण कर तार्किक नहीं था। इसे शायद यूनिट के स्तर पर कर लगाने के लिए चालू किया गया था। आदर्श रूप में इसका भुगतान टैक्स स्लैब के मुताबिक प्राप्तकर्ता की तरफ से होना चाहिए। एनएसई में यह कार्यक्रम ऋण प्रतिभूतियों के लिए आरएफक्यू प्लेटफॉर्म की पेशकश के लिए आयोजित हुआ।

शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कंपनियों पर लागू लाभांश वितरण कर की समाप्ति का ऐलान किया था और कहा था कि अब लाभांश पर कर प्राप्तकर्ता को चुकाना होगा।

इस कदम पर बाजार ने मिश्रित प्रतिक्रिया जताई। लाभांश वितरण की समाप्ति से कंपनियों को 20 फीसदी कर की बचत होगी, लेकिन प्रवर्तकों और अन्य धनाढ्य शेयरधारकों से लाभांश पर 43 फीसदी तक कर वसूला जा सकता है। विश्लेषकों का मानना है कि कंपनियां अब लाभांश देने के बजाय शेयर पुनर्खरीद की ओर बढ़ेंगी।

वैश्विक स्तर पर अलग-अलग तरह से लाभांश पर कर वसूला जाता है। अमेरिका व जर्मनी में लाभांश पर विदहोल्डिंग कर लगाया जाता है, वहीं ब्रिटेन और सिंगापुर जैसे बाजारों में ऐसा नहीं होता।

इस बीच, त्यागी ने कहा कि सेबी ने फ्रैंकलिन टेम्पलटन म्युचुअल फंड से पूछा है कि रेटिंग एजेंसियों की तरफ से किसी तरह की कवायद से पहले वोडाफोन आइडिया के ऋणपत्र में निवेश को बट्टे खाते में क्यों डाला गया। उन्होंने कहा, अगर यह परिसंपत्ति निवेश श्रेणी से नीचे नहीं है तो इस तरह का कदम नहीं उठाया जाना चाहिए। हमने फंड हाउस से इस पर अपना पक्ष रखने को कहा है।

पिछले महीने फंड हाउस ने एजीआर पर दूरसंचार ऑपरेटरों की समीक्षा याचिका खारिज किए जाने के तत्काल बाद वोडाफोन आइडिया के ऋणपत्र में 100 फीसदी निवेश को बट्टे खाते में डाल दिया था। फ्रैंकलिन का कदम यूटीआई एमएफ, निप्पॉन एमएफ और बिड़ला एमएफ से अलग था, जिन्होंने रेटिंग एजेंसियों की तरफ से उपलब्ध कराए गए मूल्यांकन मानक के मुताबिक निवेश को बट्टे खाते में डाला। त्यागी ने यह नहीं बताया कि क्या सेबी ने अन्य फंड हाउस से भी इस बारे में जानकारी मांगी है।

एलआईसी की प्रस्तावित शेयर बिक्री पर त्यागी ने कहा कि बीमा कंपनी को सूचीबद्ध कराने वाली अन्य कंपनी की तरह ही पूरी प्रक्रिया का पालन करना होगा। इस पर हालांकि उन्होंने और टिप्पणी से इनकार कर दिया।

टाइटन ने पूर्व एमडी को 25 करोड़ रु. चुकाए

बीएस संवाददाता
बेंगलूरु, 4 फरवरी

आभूषण एवं घड़ी निर्माता टाइटन ने अपने पूर्व प्रबंध निदेशक भास्कर भट को विशेष सेवानिवृति लाभ के तौर पर 25 करोड़ रुपये का भुगतान किया है।

बेंगलूरु में मुख्यालय वाली इस कंपनी ने कहा है, '31 दिसंबर 2019 को समाप्त तिमाही के दौरान निदेशक मंडल ने प्रबंध निदेशक को कंपनी की नीति के अनुसार देय विशेष सेवानिवृत्ति लाभ चुकाने को मंजूरी दी थी। भट सितंबर 2019 में सेवानिवृत हुए।' भट कंपनी बोर्ड में गैर-कार्यकारी गैर-स्वतंत्र निदेशक के तौर पर काम करते रहेंगे।

ब्रांड कंसल्टेंट हरीश बिजूर ने कहा, 'यह उनके द्वारा टाइटन के लिए दिए गए योगदान के लिए विशेष सम्मान है।' भट लगभग 36 वर्षों तक टाइटन के साथ जुड़े रहे। टाटा समूह के इस संयुक्त उपक्रम ने दिसंबर तिमाही में कर्मचारी लाभ खर्च में लगभग 77 करोड़ रुपये का इजाफा दर्ज किया। कंपनी ने 648 करोड़ रुपये का कर-पूर्व लाभ दर्ज किया, जो पूर्ववर्ती वित्त वर्ष की समान तिमाही के मुकाबले लगभग 8 प्रतिशत की वृद्धि है। समान अवधि में शुद्ध समेकिन लाभ में सालाना आधार पर 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई। दिसंबर तिमाही के दौरान समेकित राजस्व वित्त वर्ष 2019 की तीसरी तिमाही की तुलना में 10 प्रतिशत तक बढ़कर 6,550 करोड़ रुपये हो गया। परिचालन मार्जिन सालाना आधार पर 20 आधार अंक बढ़कर 10.6 प्रतिशत पर रहा।

कंपनी के विभिन्न सेगमेंट्स में शामिल आभूषण व्यवसाय ने तीसरी तिमाही में पिछले साल के मुकाबले 10.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।

कंपनी के प्रबंध निदेशक सी के वेंकटरमन ने कहा, 'शादियों के सीजन की वजह से हमारे आभूषण व्यवसाय के लिए खुदरा वृद्धि तीसरी तिमाही में मजबूत रही। आखिरी तिमाही में कई नए उत्पाद पेश किए जाने हैं और हम अपने ब्रांडों में निवेश बरकरार रखेंगे और ग्राहकों को आकर्षक उत्पादों का अनुभव मुहैया कराएंगे।'

एक्सेंचर ने खोला नवोन्मेष केंद्र

बीएस संवाददाता
हैदराबाद, 4 फरवरी

परामर्श एवं पेशेवर सेवा प्रदाता अमेरिकी कंपनी एक्सेंचर ने हैदराबाद में अपना नया इनोवेशन हब खोला है। यह इनोवेशन हब 3 लाख वर्ग फुट में फैला हुआ है।

कंपनी के वैश्विक नवाचार के नेटवर्क में शामिल हुए इस नए हब से 200 पेशेवर जुड़े हुए हैं। ये पेशेवर विभिन्न उद्योगों की दक्षता और आर्टीफिशियल इंटेलीजेंस सिक्युरिटी, एक्सटेंडेड रियलिटी, ऑटोमेशन और ब्लॉकचेन जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों का अनुभव रखते हैं। बेंगलूरु के बाद भारत में यह एक्सेंचर का दूसरा केंद्र है।

एक्सेंचर टेक्नोलॉजी सर्विसेज के समूह मुख्य अधिकारी भास्कर घोष ने कहा, 'हमारे शोध से पता चलता है कि प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश और क्रियान्वयन के लिए उद्यम-केंद्रित रणनीति के अभाव की वजह से संगठनों को अपने नवाचार लक्ष्यों को हासिल करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है।' उन्होंने दावा किया कि नया इनोवेशन हब उनके ग्राहकों के लिए उद्यम-आधारित नवाचार के जरिये वैल्यू बढ़ाने के लिहाज से महत्वपूर्ण होगा।

इस नए केंद्र में एशिया-प्रशांत क्षेत्र में एक्सेंचर की पहली नैनो लैब भी है। यह हब ग्राहकों को वैश्विक रूप से एक्सेंचर लैब्स के व्यवहार्य शोध की नई सफलताओं से भी अवगत करा रहा है। नैनो लैब कई नई प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल को प्रदर्शित करती है।

बीएस बातचीत

बजट के बाद वृद्धि और आय पर रहेगा जोर

नोमुरा में इंडिया इक्विटी रणनीतिकार **सायन मुखर्जी** ने **समी मोडक** को दिए साक्षात्कार में कहा कि विदेशी पूंजी आकर्षित करना, निवेश-आधारित वृद्धि और आक्रामक तौर पर विनिवेश बजट में उभरते मुख्य थीम हैं। मुखर्जी का कहना है कि कोरोनावायरस की आशंका से प्रभावित एशियाई प्रतिस्पर्धियों के बीच भारतीय बाजार अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में दिख रहे हैं। पेश हैं उनसे हुई बातचीत के मुख्य अंश:

बजट की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?
मुख्य थीम यह हे कि सरकार अपनी स्थिति मजबूत बनाने के लिए परिसंपत्तियों की बिक्री कर रही है। विनिवेश में बड़ी तेजी आई है। यदि आपका राजस्व संग्रह कम है तो आपके पास विकास संबंधित खर्च के लिए सीमित संसाधन हैं। इसलिए आपको गैर-कर राजस्व का सहारा लेना होगा। सरकार के पास बड़ी तादाद में मूल्यवान परिसंपत्तियां हैं जिनकी बिक्री की जा सकती है। 2.1 लाख करोड़ रुपये का विनिवेश लक्ष्य एक बड़ी पहल है। हमने इस संदर्भ में इतना बड़ा आंकड़ा कभी नहीं देखा। क्रियान्वयन महत्वपूर्ण होगा। अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने निवेश-केंद्रित वृद्धि पर ध्यान केंद्रित किया है और विदेशी पूंजी आकर्षित करने के प्रयास कर रही है। घरेलू बचत कमजोर हुई है, क्योंकि अर्थव्यवस्था की गति सुस्त हुई है। इसलिए आपको वृद्धि के लिए विदेशी पूंजी की जरूरत है।

बजट को लेकर बाजार की प्रतिक्रिया नकारात्मक थी? क्या भारतीय बाजार पर आपने अपना नजरिया बदलाव है?
हमने अपना कीमत लक्ष्य नहीं बदला है। बजट से कई तरह की उम्मीदें हैं। यही वजह है कि बिकवाली देखी गई। इसके अलावा, कोरोनावायरस को लेकर आशंका ने भी इसमें योगदान दिया है। बाजार में फिर से तेजी आई है और कई कंपनियों के शेयर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्य फोकस फिर से वृद्धि और आय पर रहेगा। उम्मीद है कि वैश्विक परिवेश अनुकूल बना रहेगा।

बजट से किस तरह का निवेश थीम उभरा है?
मौजूदा समय में कोई नया थीम नहीं है। एकमात्र बदलाव बीमा को लेकर था। आज आप बीमा में निवेश कर सकते हैं और कर लाभ ले सकते हैं। लेकिन हम मौजूदा समय में जिस दिशा में जा रहे हैं, उसमें लाभ हासिल नहीं हो सकता है। इसलिए यह प्रवाह के दृष्टिकोण से नकारात्मक है। अन्य पहलू डीडीटी है। इसकी समाप्ति के बाद प्रभावी कर दर बीमा कंपनियों के लिए बढ़ गई है।

डीडीटी हटने का कॉरपोरेट की वित्तीय स्थिति पर क्या असर पड़ेगा?
अब सवाल यह है कि क्या कंपनियां लाभांश बढ़ाएंगी या कर बचत पर जोर देंगी। यदि किसी कंपनी को पूंजी की जरूरत होती है तो इसके लिए उसे अतिरिक्त पूंजी बनाए रखना जरूरी होगा। पूंजी की जरूरत महसूस नहीं करने वाली कंपनियां भुगतान बढ़ा सकती हैं। प्रवर्तक के नजरिये से, कर-किफायती विकल्प पुनर्खरीद हो सकता है। इसलिए, मैं यह उम्मीद करूंगा कि बड़ी तादाद में कंपनियां पुनर्खरीद की घोषणा करेंगी। विदेशी निवेशक के दृष्टिकोण से, आपने कर उद्देश्य से परिसंपत्तियों को अधिक आकर्षक बनाया है।

आपके हिसाब से आय वृद्धि की रफ्तार कैसी रहेगी?
कुछ अनुकूल परिस्थितियां बरकरार हैं। हर साल हम आय में 15 प्रतिशत की कमी कर रहे हैं। यदि आप कॉरपोरेट कर कटौती को समायोजित करें तो यह अनुमानों से 15 प्रतिशत कम है। दिलचस्प बात यह है कि आय कटौती की तीव्रता अर्थव्यवस्था में मंदी के बीच पिछले कैलेंडर वर्ष की दूसरी छमाही में बढ़ गई थी। अब दूरसंचार में कीमतों में सुधार, एनपीए में सुधार हो चुके हैं। इस सबसे मदद मिल रही है। अब हम वैश्विक रूप से हालात में सुधार देख सकते हैं। यदि जिंस कीमतें नीचे आती हैं तो धातु जैसे क्षेत्रों पर असर दिख सकता है। मेरा मानना है कि वित्त वर्ष 2021 और वित्त वर्ष 2022, दोनों के लिए आय अनुमानों में 5 प्रतिशत की कमी देखी जा सकती है।

आईओसी ने इजरायल की कंपनी में ली हिस्सेदारी

भाषा
नई दिल्ली, 4 फरवरी

सार्वजनिक क्षेत्र की इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) ने इजराइल की बैटरी बनाने वाली कंपनी फिनर्जी में छोटी हिस्सेदारी खरीदी है। यह हिस्सेदारी बहुत कम वजन के मेटल-एयर बैटरी के विनिर्माण के लिए खरीदी गई है। इस बैटरी का उपयोग इलेक्ट्रिक वाहनों में किया जा सकता है। कंपनी एक बयान में कहा, आईओसी ने फिनर्जी में अल्पांश हिस्सेदारी खरीदी है। हालांकि कंपनी ने यह नहीं बताया कि उसने कितनी हिस्सेदारी खरीदी है और उसके लिए कितना भुगतान किया है। वर्ष 2008 में बनी फिनर्जी शून्य उत्सर्जन वाली बैटरी बनाती है। इसमें एल्युमीनियम-एयर और जिंक-एयर बैटरी शामिल हैं। इस बैटरी का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक वाहनों में किया जा सकता है।

आईओसी और फिनर्जी भारत में संयुक्त उद्यम बनाएंगी। संयुक्त उद्यम इकाई एल्युमीनियम-एयर बैटरी प्रणाली का विकास करेगी। इसमें शोध और विकास, जरूरत के अनकूल बनाना, विनिर्माण आदि शामिल हैं। बयान के अनुसार, संयुक्त उद्यम के तहत भारत में एल्युमीनियम एयर बैटरी के विनिर्माण के लिए कारखाना लगाया जाएगा। फिनर्जी के पास एल्युमीनियम-एयर और जिंक-एयर बैटरी में विशेषज्ञता है। इस प्रकार की बैटरी का उपयोग वाहनों और अन्य कार्यों में किया जा सकता है।

भारतीय बाजार पर बड़ा दांव लगा रही ट्रूकॉलर

बीएस संवाददाता
नई दिल्ली, 4 फरवरी

कॉलर पहचान सेवा प्रदाता ट्रूकॉलर भारतीय बाजार पर बड़ा दांव लगा रही है। कंपनी ने इस साल यहां कई वित्तीय सेवा उत्पाद पेश करने की योजना बनाई है। ट्रूकॉलर के प्रबंध निदेशक संदीप पाटिल का कहना है कि कंपनी पिछले चार महीनों से मुनाफे में बनी हुई है और दुनियाभर में उसके मासिक सक्रिय उपयोगकर्ताओं (एमएयू) की संख्या 20 करोड़ को पार कर गई है। इनमें से 14 करोड़ उपयोगकर्ता भारत में हैं। उन्होंने कहा, 'हमारे कुल उपयोगकर्ताओं में भारत का योगदान 70 प्रतिशत है। यह देश अभी भी तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। हमने भारत में पिछले साल मोबाइल फोन की पहुंच बढ़ने से 23 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।'

ग्रैन्युल्स इंडिया ने बेची ग्रैन्यूल्स बायोकॉज की हिस्सेदारी

ग्रैन्यूल्स इंडिया ने चीन में बनाए अपने संयुक्त उपक्रम ग्रैन्यूल्स-बायोकॉज फार्मास्युटिकल्स की पूरी हिस्सेदारी बेच दी है। कंपनी ने बताया कि उसने यह सौदा करीब 110.8 करोड़ रुपये में पूरा किया है। कंपनी ने कहा कि ग्रैन्यूल्स बायोकॉज फार्मास्युटिकल्स कंपनी अब ग्रैन्यूल्स इंडिया का संयुक्त उद्यम नहीं है। *भाषा*

यामाहा ने बीएस-6 वाहन पेश किया

इंडिया यामाहा मोटर प्राइवेट लि. ने मंगलवार को भारत चरण-छह (बीएस-छह) उत्सर्जन मानक अनुकूल एफजेड-25 मोटरसाइकिल उतारी। इसके साथ ही कंपनी ने पूरी तरह नई एफजेडएस- 25 बाइक का भी अनावरण किया। *भाषा*

छोड़ भी सकेंगे वैकल्पिक आयकर व्यवस्था!

दिलाशा सेठ
नई दिल्ली, 4 फरवरी

बजट के बाद उद्योगों से बातचीत में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन पीसी मोदी ने आज साफ किया कि व्यक्तिगत करदाताओं को अपनी सुविधा के मुताबिक सालाना आधार पर नई व पुरानी कर दरों को अपनाने की स्वतंत्रता होगी। उन्होंने कहा कि सरकार सभी छूट व कटौती चरणबद्ध तरीके से खत्म करने को इच्छुक है, जिससे करदाता अपने को परेशानी में पाता है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश की गई नई कर व्यवस्था के लाभ को बताते हुए मोदी ने कहा कि विकल्प मिलने से वेतनभोगी वर्ग को भी फायदा होगा और यह सही वक्त है कि पूरी व्यवस्था पर नए सिरे से विचार किया जाए।

मोदी ने एसोचेम के एक कार्यक्रम में कहा, 'करदाताओं को पुराने व नए व्यक्तिगत आयकर दरों को सालाना आधार पर चुनने का विकल्प होगा। करदाताओं के लिए कर ढांचा सरल बनाया गया है। मुझे लगता है कि यह सही वक्त है, जब पूरी व्यवस्था पर फिर से विचार किए जाने की जरूरत है और युवा लोग जो छूट और कटौती का लाभ नहीं पाते हैं, उनके लिए कम दरें आकर्षक होंगी।' उन्होंने कहा कि हमें युवा पीढ़ी को फैसला करने देना चाहिए कि वे अपना धन खर्च करना चाहते हैं या बचाना चाहते हैं।

दो दरों में से एक का विकल्प चुनने और फिर से पहले वाली व्यवस्था में वापस जाने का विकल्प बहरहाल सिर्फ व्यक्तिगत या हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) के लिए होगा, जिनकी कारोबार से आमदनी नहीं है।

बजट ज्ञापन में कहा गया है कि कि जिन लोगों की कारोबार से आमदनी है, उन्हें एक बार कम कर का विकल्प चुनने के बाद पुराने दौर में वापस लौटने का विकल्प नहीं मिलेगा।

प्रस्ताव के मुताबिक 70 कर छूटों को हटाया जाएगा और 5 लाख से 7.5 लाख रुपये आमदनी वालों पर 10 प्रतिशत कर लगेगा, जो मौजूदा 20 प्रतिशत से कम है। वहीं 7.5 लाख से 10 लाख रुपये आमदनी पर 15 प्रतिशत कर लगेगा, जो मौजूदा 20 प्रतिशत से कम है। वहीं 10 से 12.5 लाख रुपये आमदनी पर 20 प्रतिशत कर लगेगा, जबकि अभी 30 प्रतिशत लगता था। 12.5 से 15 लाख रुपये सालाना आमदनी पर 25 प्रतिशत कर होगा, जबकि अभी 30 प्रतिशत लगता है। 15 लाख रुपये से ज्यादा आमदनी वालों पर 30 प्रतिशत कर लागू रहेगा।

सीतारमण ने सितंबर में घोषणा की थी कि मौजूदा कंपनियों के लिए कर दर 25-30 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत की जाएगी, जो किसी तरह की छूट नहीं लेते है। लेकिन कम कर दर का विकल्प चुन चुके कॉर्पोरेट्स को पुराने कर का विकल्प अपनाने की अनुमति नहीं होगी।

कर ढांचे को सरल बना रही सरकार

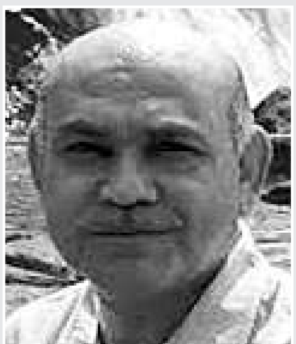

- व्यक्तिगत करदाताओं को अपनी सुविधा के मुताबिक सालाना आधार पर नई व पुरानी कर दरों को अपनाने की स्वतंत्रता होगी
- सरकार की कवायद है कि युवाओं को अपनी इच्छा के मुताबिक पैसे बचाने या खर्च करने का विकल्प मिले
- कम कर दर का विकल्प चुन चुकी कंपनियों को पुराने कर का विकल्प अपनाने की अनुमति नहीं

जीएसटी भुगतान करने वालों के लिए लॉटरी योजना

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीआईसी) के अंतरिम चेयरमैन जॉन जोसेफ ने कहा कि सरकार जीएसटी कर का भुगतान करने वालों के लिए एक लॉटरी योजना पर काम कर रही है, जिससे अनुपालन में सुधार हो सके। इसमें जीतने वाली राशि 10 लाख रुपये से एक करोड़ रुपये के बीच होगी। इस कदम का मकसद कर संग्रह बढ़ाना है, जो चालू वित्त वर्ष में आर्थिक मंदी और फर्जी इनवाइस के चलते लक्ष्य से पीछे चल रहा है। जोसेफ ने कहा, 'करदाता के हर जीएसटी बिल पर ईनाम जीतने वाली लॉटरी का टिकट होगा।'

अधिकारी ने कहा कि लॉटरी योजना दिल्ली सरकार के मूल्यवर्धित कर के दौर में ग्राहकों को दिए गए प्रोत्साहन की तर्ज पर होगा। दिल्ली सरकार ने मूल्यवर्धित कर के समय में 2015 में बिल बनाओ ईनाम पाओ योजना शुरू की थी।

सरकारी बैंकों के विलय को आज मिल सकती है सरकार की मंजूरी

सोमेश झा
नई दिल्ली, 4 फरवरी

केंद्र सरकार बुधवार को सार्वजनिक क्षेत्र के 10 बैंकों को मिलाकर 4 बैंक बनाने की योजना को मंजूरी दे सकती है। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक बुधवार को होनी है। उम्मीद की जा रही है कि इसमें बैंकों के विलय की योजना को मंजूरी दी जा सकती है, जो इस प्रक्रिया की दिशा में एक और अहम कदम होगा।

मंत्रिमंडल के सामने मंजूरी के लिए रखी गई योजना के मुताबिक 1 अप्रैल 2020 तक बैलेंस सीट के विलय की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। उसके बाद सभी 10 सरकारी बैंकों के बोर्डों की बैठक होगी और वह स्वैप रेश्यो को मंजूरी देंगे।

इस योजना में बैंकों के कर्मचारियों के हितों की रक्षा के भी प्रावधान होंगे। इसमें कहा गया है कि बैंक के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते की राशि विलय के पहले मिलने वाली राशि की तुलना में कम नहीं होगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगस्त 2019 में विलय की घोषणा की थी, जो विलय की सबसे बड़ी कवायद होगी।

10 बैंकों का विलय

पंजाब नैशनल बैंक, ओरिएंटल बैंक आफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया को मिलाकर देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक बनेगा। केनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक का विलय, यूनियन बैंक आफ इंडिया में आंध्र बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का विलय और इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक का विलय होगा।

एक सरकारी बैंक के शीर्ष अधिकारी ने कहा कि सरकार की विलय संबंधी अधिसूचना के बाद बैंक प्रक्रिया पूरी करने में 6-7 सप्ताह का वक्त लेंगे। अल्पांश शेयरधारकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार 'शिकायत निवारण समिति' का गठन करेगी। अल्पांश शेयरधारकों को अपनी चिंता सामने रखने के लिए 21 दिन का वक्त दिया जाएगा।

केंद्रीय बजट 2020-21 में सरकार ने विलय होने जा रहे इन बैंकों को अपने नुकसान और मूल्यह्रास को आगे बढ़ाने की अनुमति दी है, जिससे इनकी कर देनदारी उल्लेखनीय रूप से कम हो जाएगी।

रविवार को वित्त सचिव राजीव कुमार ने कहा था, 'विलय होने जा रहे बैंकों के घाटे को आगे बढ़ाने की अनुमति दी गई है। यह बड़ी राहत होगी। उदारहण के लिए जब देना बैंक का विलय बैंक आफ बड़ौदा में किा गया था तो उसका पूरा नुकसान अगले के खाते में चला गया था।' विलय होने जा रहे 10 सरकारी बैंकों की यह प्रमुख मांग थी।

बिजली क्षेत्र ने लगाया कम कोयला देने का आरोप

श्रेया जय
नई दिल्ली, 4 फरवरी

नई शक्ति नीलामी के तहत कोयले के लिए बोली लगाने की योजना बना रही दबावग्रसत बिजली परिसंपत्तियों ने अब राष्ट्रीय खनन कंपनी के खिलाफ मांग से कम कोयला देने की शिकायत की है। बिजली उद्योग ने कोल इंडिया पर आरोप लगाया है कि उसने ऐसा कोयले की अधिसूचित कीमत को नीलामी में 100 फीसदी अधिक तक ऊपर उठाने के लिए किया है।

कोयला नीलामी का दूसरा चरण उन दबावग्रस्त बिजली परियोजनाओं के लिए है जिनके पास कोई कोयला लिंकेज और बिजली बेचने के लिए बिजली खरीद समझौता (पीपीए) नहीं है। कोयला आपूर्ति की कमी वाली दबावग्रस्त बिजली इकाइयों को कोयला मुहैया कराने के लिए 2018 में शक्ति यानी स्कीम फॉर हारनेसिंग स्कीम फॉर हारनेसिंग ऐंड एलोकेटिंग कोयला ट्रांसपेरेंटली इन इंडिया की शुरुआत हुई थी।

पहले चरण में अपनी बिजली बिक्री दर को घटाने के बदले 7,620 मेगावॉट की क्षमता वाली कंपनियों को कोयला मिला था। इसके अगले चरण की शुरुआत फॉरवॉर्ड ऑक्शन प्रक्रिया के तहत बुधवार को होगी। कंपनियां कोल इंडिया और उसकी सहायक कंपनियों की ओर से पेश किए जाने वाले कोयले की मात्रा के लिए बोली लगाएंगी और उच्चतम बोलीदाता जीतेंगे।

उद्योग ने अब शिकायत की है कि कोल इंडिया द्वारा दिया जा रहा कोयला मांग की 50 फीसदी से भी कम है। 8,000 मेगावॉट की परियोजनाओं के लिए कोयले की 4 करोड़ टन की अनुमानित मांग के बदले कोल इंडिया ने 1.1 करोड़ टन कोयले की पेशकश की है। उद्योग के अधिकारी ने कहा, 'कोयल की पेशकश में की गई इस कमी से कोल इंडिया को कम से कम 500 करोड़ रुपये का प्रीमियम हासिल होगा।'

उन्होंने कहा कि यह एक दोषपूर्ण नीलामी प्रक्रिया है। उन्होंने कहा, 'इस नीलामी प्रक्रिया को शुरू करने का निर्णय लेने से पहले कम से कम कोयला और विद्युत मंत्रालय को साझेदारों से बाजार की प्रतिक्रिया की जांच कर लेनी चाहिए थी।'

उनका विरोध इस मुद्दे पर भी है कि बोलीदाताओं को दीर्घ या मध्यम अवधि का पीपीए मिल जाने के बाद कोयले का इस्तेमाल केवल वे ही कर सकते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय को लिखे एक पत्र में उद्योग की प्रतिनिधि निकाय एसोसिएशन ऑफ पावर प्रोड्यूसर्स (एपीपी) ने कहा कि मुख्य तौर पर नीलामी की रूपरेखा कोयला कंपनी के राजस्व में बढ़ोतरी करने के लिए किया गया है। बिजनेस स्टैंडर्ड ने पत्र की समीक्षा की है। पत्र में कहा गया है, 'कोयल के इस्तेमाल को दीर्घावधि या मध्यावधि के पीपीए तक कोयले के इस्तेमाल को सीमित करने का काई औचित्य नहीं है। सफल बोलीदाता को बाजार में मौजूद किसी भी व्यवस्था के तहत बिजली बनाने के लिए कोयले के इस्तेमाल की स्वतंत्रता होनी चाहिए।'

कोल इंडिया के अधिकारी ने कहा कि कंपनी इन आरोपों को खारिज करती है। अधिकारी ने कहा, 'कोल इंडिया बिजली के लिए कोयले के लिंकेज की नीलामी सरकार की ओर से समय समय पर बनाई गई नीतियों और दिशानिर्देशों के मुताबिक करती है। कोल इंडिया सरकार की एक जिम्मेदार इकाई है और उसने पेशकश में किसी भी तरह का बदलाव करने का प्रयास नहीं किया है।'

एपीपी ने प्रधानमंत्री कार्यालय से अनुरोध किया, 'यदि स्पष्ट त्रुटियों के बावजूद इस योजना को जारी रखा जाता है तो हमारा सुझाव है कि नीलामी के जरिये पेश किए गए कोयले पर प्रतिबंधित इस्तेमाल की शर्तों को हटाना जरूरी है।'

शक्ति नीलामी आई

कंपनियां	अधिसूचित कीमत रुपये प्रति टन
एसईसीएल	955
सीसीएल	955
ईसीएल	3,000
एमसीएल तलचर	817
बीसीसीएल	2,600
एनसीएल	1,024
एनसीएल आईबी वैली	817
डब्ल्यूसीएल	1,768

सूत्रः उद्योग

लोकसभा में वायुयान संशोधन विधेयक पेश

एजेंसियां
नई दिल्ली, 4 फरवरी

सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में वायुयान संशोधन विधेयक 2020 पेश किया जिनमें नियमों के उल्लंघनों के मामले में जुर्माने की अधिकतम सीमा को वर्तमान 10 लाख रुपये से बढ़कर एक करोड़ रुपये कर दिया गया है। वायुयान संशोधन विधेयक 2020 में नौसेना, थल सेना या वायु सेना से भिन्न संघ के सशस्त्र बलों से संबंधित वायुयानों को वायुयान अधिनियम 1934 के कार्य क्षेत्र से बाहर रखने का प्रावधान किया गया है।

संशोधन पारित कर दिए जाने के बाद सरकार को शक्ति होगी कि वह नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए), ब्यूरो आफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी (बीसीएएस) और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंड इन्वेस्टीगेशन ब्यूरो (एआईआईबी) द्वारा पारित किसी भी आदेश का जनहित में जरूरी होने पर समीक्षा कर सकती है। ऐसा इस विधेयक के उद्देश्य व वजहों में उल्लिखित है।

इसमें प्रमुख प्रस्ताव उल्लंघन के मामले में जुर्माने की राशि 10 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये किया जान है। अन्य प्रस्तावों में बीसीएएस को ताकतवर बनाना या किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिशानिर्देश देने का अधिकार दिया जाना शामिल है।

निचले सदन में संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक पेश किया।

दबाव से जूझ रहे हैं छोटे व मझोले उद्यम

नम्रता आचार्य
कोलकाता, 4 फरवरी

सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम (एमएसएमई) इस समय भुगतान में देरी और मांग सुस्त रहने के संकट से जूझ रहे हैं। सरकार ने पुनर्गठन की अंतिम तिथि एक साल और बढ़ा दी है, इसके बावजूद यह क्षेत्र दबाव में बना हुआ है।

बैंकों और एमएसएमई के मुताबिक बड़ी संख्या में ऐसे मामले हैं, जिसमें पुनर्भुगतान में एक महीने से ज्यादा और यहां तक 120 दिन की देरी हुई है। बैंकों को उन कर्ज को गैर निष्पादित संपत्ति में डालना होता है, अगर इसका भुगतान करने में 90 दिन की देरी होती है।

एसएमई चैंबर आफ इंडिया के अध्यक्ष चंद्रकांत सालुंखे ने कहा, 'एमएसएमई क्षेत्र में भुगतान में देरी चिंता का प्रमुख विषय है। इसके अलावा एमएसएमई अपने खरीदार से टकराव नहीं चाहती हैं, क्योंकि मांग स्थिर है। पुनर्गठन की कवायद फायदेमंद हो सकती है, लेकिन बैंक खातों के पुनर्गठन के इच्छुक नहीं है। परिणामस्वरूप एमएसएमई को जिंदा रहने के लिए जूझना पड़ रहा है।'

मांग स्थिर रहने और दबाव के साथ इस क्षेत्र में कर्ज की वृद्धि दर भी स्थिर है। रिजर्व बैंक के आंकड़ों से पता चलता है कि सूक्ष्म और लघु क्षेत्र में कर्ज की वृद्धि चालू वित्त वर्ष के नवंबर महीने तक -3.4 प्रतिशत रही है। वहीं मझोले उद्यों में यह -3.6 प्रतिशत है। पिछले साल की तुलना में भी सूक्ष्म-लघु एवं मझोले क्षेत्रों में कर्ज की वृद्धि दर नवंबर 2019 तक क्रमशः -0.1 प्रतिशत और -2.4 प्रतिशत रही है।

जनवरी 2019 में भारतीय रिजर्व बैंक चूक करने वाले एमएसएमई को एकमुश्त पुनर्गठन की अनुमति दी थी, जो 1 जनवरी तक गैर निष्पादित नहीं हैं। इसकी मूल अंतिम तिथि 31 मार्च 2020 रखी गई थी, जिसे हाल के केंद्रीय बजट में बढ़ाकर 31 मार्च 2021 कर दिया गया है। बैंकों के मुताबिक करीब 2 लाख करोड़ रुपये एमएसएमई कर्ज को 31 मार्च 2020 तक पुनर्गठित करने के लिए चिह्नित किया गया। सूत्रों के मुताबिक बैंकों को उम्मीद है कि वे अपना 70 प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर लेंगे।

सरकारी बैंक के एक वरिष्ठ बैंकर ने कहा कि जहां बैंक एमएसएमई खातों के पुनर्गठन को इच्छुक हैं, कुछ मामलों में पुनर्गठन व्यावहारिक नहीं है क्योंकि इसका मतलब उसे एनपीए बनाना है। ट्रांस यूनियन सिबिल के आंकड़ों से पता चलता है कि एमएसएमई क्षेत्र में एनपीए की दर सितंबर 2018 के 11.7 प्रतिशत से बढ़कर सितंबर 2019 में 12.2 प्रतिशत हो गई है।

फेडरेशन आफ स्माल ऐंड मीडियम इंडस्ट्रीज, पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष विश्वनाथ भट्टाचार्य के मुताबिक, 'कॉर्पोरेट के भुगतान न करने से एमएसएमई क्षेत्र दबाव में है। मांग ठहर गई है और बैंक भी कर्ज बढ़ाने को तैयार नही हैं।'

एक अन्य सरकारी बैंक के शीर्ष अधिकारी ने कहा, 'हम देख रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा एमएसएमई पुनर्गठन के लिए आगे आ रहे हैं। बहरहाल हमें कुछ बदलाव करने की जरूरत हो सकती है, जिससे पुनर्गठन ज्यादा आकर्षक और व्यावहारिक बन सके।' एकमुश्त पुनर्गठन के अलावा सरकार ने इस क्षेत्र में कर्ज बढ़ाने के लिए कुछ और कदमों की भी घोषणा की है।

सरकार के कदमों से राहत नहीं!

- सरकार ने एमएसएमई के कर्ज के पुनर्गठन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 मार्च 2021 कर दी है
- एसएमई क्षेत्र का कहना है कि सुस्त मांग और कंपनियों से भुगतान न मिलने से संकट
- मांग सुस्त होने के कारण भुगतान को लेकर सख्ती भी नहीं दिखा पा रहे उद्यमी

बीएस बातचीत

ज्यादा उत्पादक क्षेत्रों पर व्यय को दी गई है प्राथमिकता

दिसंबर के मध्य व्यय सचिव **टीवी सोमनाथन** ने वित्त मंत्रालय में नया पद संभाला था, जब बजट की तैयारियां जोरों पर थीं। **अरूप रॉयचौधरी** से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार मनरेगा और पीएम-किसान जैसी प्रमुख ग्रामीण योजनाओं को जरूरत पड़ने पर ज्यादा धन मुहैया कराएगी और उन क्षेत्रों में व्यय पर जोर होगा, जिससे वृद्धि और खपत में जल्द से जल्द तेजी लाने में मदद मिले। प्रमुख अंश...

आपके मुताबिक बजट के आंकड़े हकीकत के कितने करीब हैं?

मुझे लगता है कि वास्तव में यह हकीकत के बहुत करीब हैं, क्योंकि न तो इसमें बहुत ज्यादा उम्मीद जताई गई है, न निराशा दिखाई गई है। अगर आप नॉमिनल जीडीपी में 10 प्रतिशत वृद्धि का उदाहरण लें तो हम वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6 से 6.5 प्रतिशत के बीच रहने और महंगाई दर 3.5 से 4 प्रतिशत के बीच की उम्मीद करते हैं। लेकिन अगर आप हाल के खुदरा महंगाई के आंकड़े देखें तो यह 5 प्रतिशत तक रहा है, हालांकि थोक महंगाई दर कुछ कम है। इस तरह से देखें तो हमारे आंकड़े हकीकत के बहुत करीब हैं। अगर आप राजस्व का अनुमान देखें तो इसके 1.2 तक बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। यह पहले के आंकड़ों के हिसाब से हासिल किए जाने योग्य है।

क्या बजट में पर्याप्त कदम उठाए गए हैं? विशेषज्ञों और यहां तक कि सरकार से जुड़े कुछ लोग सालाना आधार पर राजकोषीय विस्तार की बात कर रहे थे, आपने ऐसा नहीं किया।

यह विस्तार है या नहीं, यह भी विभाजक पर निर्भर होता है। बढ़ती अर्थव्यवस्था में समग्र हिसाब से 3.5 प्रतिशत, 3.8 प्रतिशत से ज्यादा है। इस तरह से कुल मिलाकर समग्र सार्वजकि व्यय अगले साल 11 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ेगा। पूंजीगत व्यय में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी।

केंद्रीय योजनाओं को तार्किक न बनाए जाने को लेकर 15वें वित्त आयोग ने सरकार की खिंचाई की है और कहा है कि सरकार को केंद्र की योजनाओं का गहराई से आकलन करना चाहिए। क्या सरकार ऐसा करेगी?

हां। हम केंद्र सरकार की ओर से प्रायोजित परियोजनाओं को तार्किक बनाने की गंभीर कवायद कर रहे हैं और यह वित्त आयोग की सिफारिशों से थोड़ा अलग है। हमारा वैसा भी करने का इरादा है। हम ऐसा विचार कर रहे हैं कि ज्यादा मूल्य के व्यय के लिए जगह बन सके और कम मूल्य के अतिरिक्त व्यय को खत्म किया जा सके। मैं पहले से आकलन नहीं करूंगा कि इस कवायद से क्या निकलकर सामने आएगा, लेकिन हम इस दिशा में गंभीर प्रयास कर रहे हैं।

क्या अगले बजट में योजनाओं की संख्या बहुत कम होने जा रही है?

मैं किसी कमी या किसी संख्या पर प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि कुछ मामलों में आप जो चाहते हैं, वह जरूरी नहीं है कि कमी ही हो। आपको कुछ मामलों में बढ़ाने की भी जरूरत होती है। तार्किक बनाए जाने में दोनों काम शामिल है। आपके पास बेहतर योजनाएं हो सकती हैं, जो धन की कमी से जूझ रही हों और बुरी योजनाओं में कटौती करने की जरूरत पड़ सकती है।

आपने इस साल पीएम-किसान से 20,600 करोड़ रुपये बचत का अनुमान लगाया था, अगर बजट अनुमान की तुलना संशोधित अनुमान से की जाए। ऐसे में फिर से वित्त वर्ष 21 के लिए 75,000 करोड़ रुपये क्यों आवंटित किए गए?

यह बढ़ोतरी इसलिए की गई है कि पहले साल में डुप्लीकेशन को छोड़ दें तो पहुंच का मसला होता है, क्योंकि योजना तेजी से शुरू की गई और बहुत तेजी से बढ़ी। ऐसे में यह संभव हो कि तमाम लोग छूट गए हों। क्योंकि विभिन्न राज्य सरकारों ने इसे पहले दौर में विभिन्न तरीकों व अलग अलग प्रशासनिक क्षमता के हिसाब से लागू किया। हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कम धन न दिया जाए क्योंकि अगर यह जरूरी है तो होना चाहिए। क्योंकि यह समाज के हाशिये पर खड़े लोगों को दिया जा रहा है।

मनरेगा के बारे में क्या कहेंगे? आपने वित्त वर्ष 21 में वित्त वर्ष 20 के संशोधित अनुमान से कम आवंटन किया?

मनरेगा मांग आधारित योजना है, ऐसे में अगर मांग बढ़ती है तो इस योजना के लिए धन मुहैया कराने की जरूरत होगी। इस साल कुछ इलाकों से मांग बढ़ी थी। आंशिक रूप से यह परिस्थितियों पर भी निर्भर होता है और इस साल कुछ राज्यों में मौसम प्रतिकूल था। अगर आने वाले साल में कुछ अप्रत्याशित घटना होती है और मांग बढ़ती है तो हम धन मुहैया कराएंगे, चाहे वह मनरेगा हो या पीएम-किसान।

बीएस सूडोकू 3656

	2		3				9	8
	8				4	3		
5		7		9				1
	7		5			1		
			8		1			
		1			7		3	
2				1		6		9
		9	4				2	
6	5				2		1	

परिणाम संख्या 3655

6	2	9	1	5	4	7	8	3
7	8	4	3	2	6	1	5	9
1	3	5	8	9	7	4	6	2
2	5	8	9	1	3	6	7	4
3	6	7	4	8	5	9	2	1
9	4	1	6	7	2	8	3	5
4	1	6	2	3	8	5	9	7
8	7	3	5	4	9	2	1	6
5	9	2	7	6	1	3	4	8

कैसे खेलें?
हर रो, कॉलम और 3 बाई 3 के बॉक्स में एक से लेकर नौ तक की संख्या भरें।

आसान ☆☆★★★

क्षेत्रीय मंडियों के भाव

उत्तर प्रदेश | राजस्थान | पंजाब

कानपुर
गेहूं लूज 2000/2010, जौ 1760/1780, चावल मसूरी 2250/2300, चावल मोटा 2200/2250, सरसों 4250/4300, तिल सफेद 8900/9000, सोया (टीन) 1500/1525, तेल सरसों कच्ची घानी वैट पेड (टीन)1450/1550,

लखनऊ
गेहूं दड़ा 2000/2010, गेहूं शरबती 2850/2950, चावल शरबती सेला 3750/3800, स्टीम 4300/4350, लालमती 3200/3250, चावल (सोना) 2800/2850,

चंदौसी
(प्रति किलो): मैन्था ऑयल 1345, बोल्ड क्रिस्टल (12 नं.)1420, फ्लैक 1365, डीएमओ 985, टरपीन लैस बोल्ड 1430

मुजफ्फरनगर
गुड़ (40 किलो): लड्डू 1000/1080, खुरपा 930/1000,चाकू 1020/1080, रसकट 900/910, शक्कर 1180/1200, चीनी मिल डिली. (क्विं.) (जीएसटी अतिरिक्त): खतौली 3300, बुंदकी 3270, बुढ़ाना 3300, शामली 3250,

हापुड़
गुड़-चीनी: चीनी हाजिर 3550/3625, गुड़ (प्रति 40 किलो) बाल्टी 940/950, तिलहन: सरसों (42 प्रतिशत कंडी.) 4200, खल: सरसों 2100/2250,

जयपुर
अनाज: चावल डीबी 5000/5200, गेहूं (मिल) 2120/2125, मक्की 2100/2115, बाजरा 1800/1810, जौ 1800/1825, ग्वार लूज 3750/3800, ज्वार कैटलफीड 2400/2500, तेल-तिलहन: सरसों(मिल पहुंच) 4375/4400, सरसों एक्सपेलर निवाई 8400,

श्रीगंगानगर
गेहूं (ढेरी) 2000/2100, ग्वार 3700/3750, जौ 2100/2125,

जोधपुर
गेहूं 2050/2100, जौ 1800/1825, पोपकोन मक्की 4400/4500, ग्वार डिलीवरी (ऑलपेड) 3900/3950, ग्वारगम 6900/7000, बाजरा (गुजरात) 1800/1825, बाजरा (जयपुर) 1825/1835, चना 4000/4100, काबली चना 5000/6000, मूंग 6900/7000,

खन्ना
जीएसटी अतिरिक्त (प्रति क्विं.): राइसब्रान (खाद्य)(प्रति प्वाइंट)107, राइसब्रान (अखाद्य) 104, खल सरसों 1900, डीओसी: राइसब्रान बैच सफेद 1000, लाल 1020, कंटीन्यूअस 1150,

लुधियाना
दाल-दलहन: राजमां चित्रा 8000/8700, अरहर दाल 7400/7900, उड़द साबुत 7300/8400, उड़द धोया 9000/9800, छिलका 8700/9300, दाल मसूर 5900/6200, चनादाल 5300/5400,

अमृतसर
चावल: बासमती (1121 नं.) स्टीम 5800/5900, सेला 5250/5300, शरबती साधारण सेला 3700/3750, शरबती स्टीम 4000/4050,चावल 1509 सेला 4950/5000, धान: शरबती 2050/2100,

बठिंडा
रुई (प्रति मन): जे-34 पंजाब 4000/4050, हरियाणा 3980/4010, राजस्थान 3960/3980, खल (प्रति क्विं.): बिनौला 2300/2400, सरसों खल 1990/2000,

फाजिल्का
गेहूं 2000/2010, सरसों 4100/4200 रुई (प्रति मन): (जे-34) 4000/4050, कपास देशी 5100/5200, कपास नरमा (क्विं.) 5000/5200, बिनौला (टैक्सपेड): खल 2400/2500,

जालंधर
गेहूं दड़ा 2000/2040, चावल परमल कच्चा 2325/2365, से ला 2260/2310, मक्की यूपी 2100/2120, दाल उड़द छिलका 8600/9700, चना देशी 4700/4750, दाल चना 5100/5150, काबली चना 5200/6100, राजमां चित्रा पुणे 7500/8900,चीन 8400/8900, शर्मिली 6000/7300,

करनाल
गेहूं दड़ा 2000/2025, बासमती चावल 6300/6400, धान 1121 नं. 2700/2750, पूसा 1509 धान 2600/2640, शरबती धान 2060/2125, सेला (1509 नं.) चावल 4950/4975, स्टीम 5800/5900,

हिसार
ग्वार 3700/3725, जौ 1840/1850, सरसों 3900/3950, मूंग 7000/7100, गेहूं 2050/2065,

जींद
जीएसटी अतिरिक्त: गेहूं 2100/2130, आटा (प्रति 44 किलो) 1040/1060, मैदा 1140/1160, देशी घी (एक ली/जार) 360/480, रिफाइंड (टीन) 1480/1500,

भिवानी
जीएसटी अतिरिक्त: सरसों 3850/3900, खल बिनौला मोटी 2150/2250, बिनौला 2600/3100, सरसों तेल 8550/8600, गेहूं 2000/2100, ग्वार 3700/3750, बाजरा 1700/1750

एनएनएस

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 301

तथ्यामक होना जरूरी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2020-21 का बजट पेश करते हुए भारत सरकार के आंकड़ों में विश्वास बहाल करने का प्रयास किया।

राजकोषीय घाटा बढ़ने, वास्तविक वृद्धि के प्रदर्शन और बेरोजगारी के स्तर को देखते हुए आंकड़ों को लेकर चिंता का माहौल बन चुका है। उन्हें यह श्रेय दिया जाना चाहिए कि उन्होंने बजट से इतर उधारी के तत्त्वों को अधिक स्पष्ट किया और सरकार ने आधिकारिक आंकड़े तैयार करने के परीक्षण के लिए एक समिति का गठन भी किया है। इससे पता चलता है कि सरकार ने यह माना है कि आधिकारिक घोषणाओं से जुड़ी विश्वसनीयता सीमित हुई है और इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। ऐसे वक्त में यह प्रयास खासा महत्त्वपूर्ण है जब निजी निवेश में आई कमी और सरकार द्वारा अतिशय व्यय के कारण आई कमी को पूरा करने के लिए विदेशी पूंजी पर निर्भरता बढ़ रही है।

विश्वसनीयता को लेकर किए जा रहे प्रयास जहां सराहनीय हैं, वहीं यह ध्यान देने लायक है कि उसे वृद्धि और बजट आंकड़ों के सवाल से आगे बढ़ना होगा। विश्वसनीयता तैयार करने में आम बजट जैसे मामले के आसपास दिए गए तमाम वक्तव्यों का योगदान होता है। अतीत में बजट भाषण में इस्तेमाल किए गए हर शब्द और हर तथ्य सत्यापित होते थे और आवश्यकता पड़ने पर उनके साथ पाद टिप्पणी दी जाती और आधिकारिक दस्तावेज से उसे बाहर भी किया जाता। बहरहाल, इस बार बजट भाषण में ऐसे कई तत्त्व शामिल थे जो साफ तौर पर ऐसी प्रक्रिया से नहीं गुजरे थे। एक शुरुआती हिस्सा जिसमें कहा गया कि वर्ष 2006 से 2016 के बीच के दशक में 27.1 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे, इसका उदाहरण है। यह आंकड़ा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की बहुआयामी गरीबी संबंधी रिपोर्ट से निकला। यदि गरीबी के आधिकारिक भारतीय आंकड़ों पर निर्भर रहा जाता तो कहीं अधिक बेहतर होता। इससे पता चलता कि सरकार अपनी सफलताओं के बारे में क्या सोचती है। इसी भाग में विभिन्न दशकों के वृद्धि और मुद्रास्फीति संबंधी आंकड़े भी दिए गए हैं जो साफ तौर पर असंगत थे। इसमें बहुत कम संदेह है कि बीते ढाई दशक में वृद्धि औसतन मजबूत रही है और हाल के वर्षों में मुद्रास्फीति पर काफी हद तक नियंत्रण हासिल किया गया है। इन बिंदुओं को बिना अनावश्यक आंकड़ेबाजी के पेश किया जा सकता था।

इसके अलावा भाषण में ऐसे भी बिंदु थे जो अवसर की गंभीरता को कम करने और सरकार को वैचारिक और अपरिपक्व दिखाने वाले थे। उदाहरण के लिए व्यापार संबंधी भाग में भाषण में कहा गया कि हड़प्पाकालीन मुहरों को पढ़ लिया गया है, सिंधुकालीन चित्र लिपि का अर्थ निकाल लिया गया है। उद्योग और वाणिज्य संबंधी शब्द दर्शाते हैं कि कैसे भारत हजार वर्षों से कौशल, धातुशोधन और व्यापार आदि में समृद्ध रहा है। सेठी नाम का उदाहरण देते हुए कहा गया कि आधुनिक भारत में यह नाम ऐसे लोगों से जुड़ा है जो पारंपरिक रूप से थोक व्यापार करते हैं। बजट भाषण में दावा किया गया कि यह नाम हड़प्पाकालीन मुहरों में भी नजर आता है। ऐसे दावों की संभवत: भलीभांति समीक्षा नहीं की गई। यह मानने की पर्याप्त वजह है कि प्राचीन भारतीय सभ्यताएं समुद्र से जुड़ी और गहन व्यापारिक गतिविधियों वाली थीं। इसके पक्ष में पर्याप्त पुरातात्विक रिकॉर्ड हैं। ऐसे दावे करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि जो बजट भाषण की गंभीरता को समाप्त करें और जिन पर लोग भृकुटियां टेढ़ी करें।

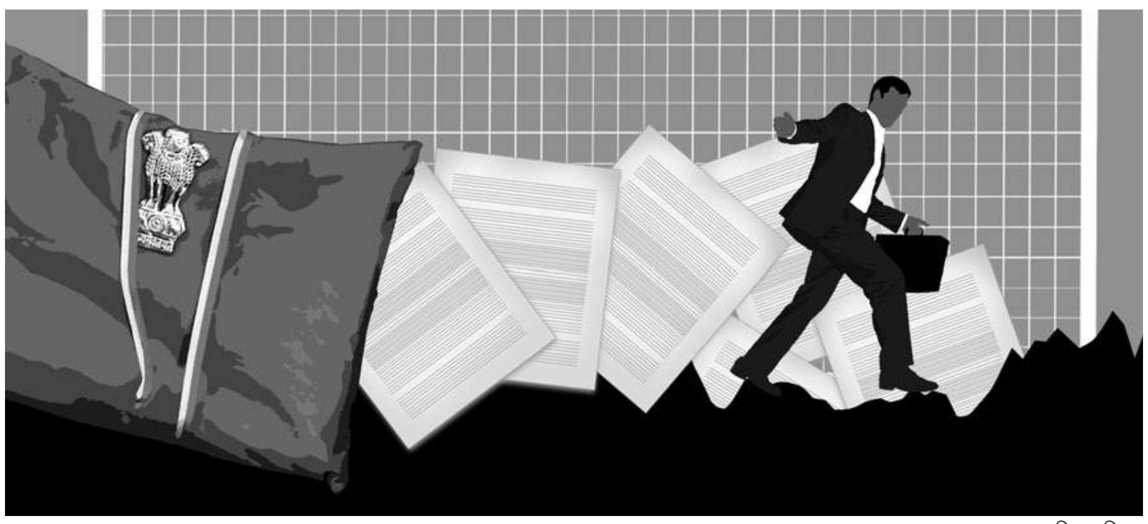

विनय सिन्हा

घाटे की भरपाई के लिए विदेशी कर्ज का रास्ता

बंधे खर्च और राजस्व की किल्लत को मद्देनजर रखते हुए घाटे की वित्त व्यवस्था के लिए वित्त मंत्री ने बेहतरीन ही किया है। इस संबंध में विस्तार से बता रहे हैं मिहिर एस शर्मा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विभिन्न चुनौतियों के बीच 2020-21 का केंद्रीय बजट तैयार किया है। अर्थव्यवस्था में अचानक बड़ी सुस्ती आई है। कर राजस्व अनुमान से सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 0.7 फीसदी कम रहने के आसार हैं। हालांकि इसमें आर्थिक मंदी और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का कितना-कितना योगदान है, उसका आसानी से निर्धारण नहीं किया जा सकता है। सरकार के लगातार चुनाव लड़ने की मुद्रा में होने और प्रधानमंत्री कार्यालय की अत्यधिक सक्रियता की वजह से बजट प्रक्रिया पर राजनीतिक दबाव बरकरार है।

हालांकि सीतारमण ने दिखाया है कि उनके पास उन हित समूहों के लिए समय नहीं है, जो विशेष या किसी क्षेत्र को लाभ देने की मांग कर रहे हैं। लेकिन इस पर विशेषज्ञों की राय बंटी हुई है कि इस समय बेहतर रणनीति क्या है- मांग को बढ़ाने के लिए कुछ समय राजकोषीय बाधाओं की अनदेखी की जाए या संकट की इस घड़ी में ढांचागत सुधारों को आगे बढ़ाते हुए राजकोषीय स्थिति को नियंत्रण में रखा जाए।

ऐसा लगता है कि वित्त मंत्री ने अपने सामने मौजूद स्थिति को देखते हुए दोनों विकल्पों के बीच का रास्ता चुना है। कागजों में राजकोषीय नियंत्रण की राह में केवल उतना ही बदलाव किया है, जितना राजकोषीय जिम्मेदारी एवं बजट प्रबंधन अधिनियम (एफआरबीएम) इसकी मंजूरी देता है। हालांकि खर्च को नियंत्रित किया गया है, लेकिन उतना नहीं, जितना राजस्व की किल्लत को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए था। ऐसे बजट को बहस के दोनों पक्षों की तरफ से 'निराशाजनक' कहा जाएगा।

निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि शेयर बाजारों ने यह निराशा दिखाई है। शेयर बाजार बजट के दिन खुले थे और उनमें कारोबार हो रहा था। हालांकि यह शनिवार का दिन था। कुछ लोगों ने उम्मीद की होगी कि बड़े राजकोषीय प्रोत्साहनों पर काम हो रहा है, जिनसे उपभोक्ता मांग में फिर सुधार आएगा और कंपनियों की आमदनी में इजाफा होगा। हालांकि मैं इस विचारधारा को लेकर अनिश्चित हूं, जो इस उम्मीद की समर्थक हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि नई जीएसटी प्रणाली में कर चोरी बड़े पैमाने पर हो रही है। अगर इस कर चोरी की वजह से जीएसटी जीडीपी के एक फीसदी तक कम बना हुआ है तो इसका क्या मतलब है? निश्चित रूप से अगर जीडीपी के अनुपात में कर 2017-18 से घट रहा है और जिसकी एक वजह जनता के हाथ में ही अप्रत्यक्ष करों का रहना है तो क्या इसे एक उतने ही बड़े प्रोत्साहन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए?

ऐसे कुछ वाजिब सवाल हैं, जो पूछे जा सकते हैं। क्या राजकोषीय घाटे को वास्तव में नियंत्रित किया गया है और उसे लक्ष्य से कम रखा जाएगा। वित्त मंत्री ने बीते वर्षों की तुलना में ज्यादा पारदर्शिता बरती है। उन्होंने कुछ अतिरिक्त बजट उधारी का खुलासा किया है और यह दिखाया है कि इससे वास्तविक राजकोषीय घाटे में कितनी बढ़ोतरी होगी। हालांकि एक तथ्य यह भी है कि अर्द्ध-सरकारी एजेंसियों की उधारी को इसमें प्रदर्शित नहीं किया गया।

हालांकि अब पहले की तुलना में यह ज्यादा साफ हो गया है कि सरकार की राजकोषीय स्थिति क्या है। यही संभवतया एक वजह है, जिससे बॉन्ड बाजार बजट को लेकर इक्विटी बाजारों से बिल्कुल अलग रुख अपना सकता है। बजट अनुमानों के मुताबिक आगामी वर्ष में सरकार की बाजार उधारी संभावित आंकड़े से कम है। सवाल यह है कि क्या बॉन्ड बाजार प्रतिक्रिया दे पाएंगे। उदाहरण के लिए यह उम्मीद करना कि विदेशी निवेशक भारतीय बॉन्डों को लपक लेंगे, असल में सही नहीं है। क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के मुताबिक इस समय विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की सामान्य श्रेणी की भारतीय प्रतिभूतियां खरीदने की सीमा 2.47 लाख करोड़ रुपये है, जिसमें से केवल 1.74 लाख करोड़ रुपये यानी करीब 70 फीसदी का इस्तेमाल हो रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पिछले महीने इसका समाधान करने की कोशिश की है। केंद्रीय बैंक ने एफपीआई के कुल निवेश में लघु अवधि की प्रतिभूतियों में लगाए जा सकने वाले अनुपात को बढ़ाया है। हालांकि एचएसबीसी के विश्लेषकों ने कहा है कि बजट की वजह से भारतीय बॉन्डों की मांग में निकट भविष्य में सुधार आने के आसार नहीं हैं। हाल के महीनों में विदेशी निवेशकों ने विशेष रूप से भारत सरकार की प्रतिभूतियों की शुद्ध बिक्री की है।

हालांकि अगर भारतीय बॉन्डों को वैश्विक बॉन्ड सूचकांकों में शामिल किया जाता है तो बड़ा फायदा मिलेगा। इससे बड़े पैसिव निवेशक भारत सरकार की घाटों की पूर्ति करेंगे। इसके पीछे यह विचार है कि इससे भारतीय घरेलू संसाधनों पर दबाव कम होगा और सरकार के घाटे को पूरा करने के लिए लघु अवधि की नकदी आवक पर निर्भरता के खतरे को टाला जा सकेगा। निश्चित रूप से यह मौजूदा तरीके राष्ट्रीय लघु बचत कोष (एनएसएसएफ) पर निर्भरता के बजाय घाटे की भरपाई का बेहतर तरीका होगा। एनएसएसएफ का खर्च के लिए पिग्गी बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, जो निश्चित रूप से सतत नहीं है। बजट में कुछ ऐसी घोषणाएं शामिल हैं, जो इस प्रयास से संबंधित लगती हैं। सीतारमण के भाषण में यह वादा भी शामिल है कि 'सरकारी प्रतिभूतियों की कुछ खास श्रेणियों को पूरी तरह प्रवासी निवेशकों के लिए खोला जाएगा।' हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि असल में इसका क्या मतलब है।

एक संबंधित सवाल यह है कि क्या कॉरपोरेट बॉन्डों को फायदा मिलेगा। मुख्य आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल ने बताया कि कैसे बाइलेटरल नेटिंग के लिए जिस कानून का वादा किया गया है, वह क्रेडिट-डिफॉल्ट स्वैप विकसित करने और इस तरह कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार को मजबूत करने में मददगार साबित हो सकता है।

कुछ स्तर पर बॉन्ड और इक्विटी बाजारों पर असर एक साथ दिखेंगे। इस समय भारत सरकार अपने संसाधनों से अधिक खर्च कर रही है। वह तेल विपणन कंपनियों, उर्वरक कंपनियों आदि को बिलों का भुगतान नहीं कर रही है। वह राज्यों को भुगतान में देरी कर रही है। सरकार बजटीय विवेकाधीन और पूंजीगत खर्च को नहीं अपना रही है। केंद्र सरकार का दो-तिहाई खर्च बंधा हुआ है, जिसमें कमी करना मुश्किल है। इस तरह राजस्व घटने का बोझ व्यय के शेष तीसरे हिस्से पड़ता है, जो कम हो रहा है। इसका आम तौर पर वित्तीय बाजारों पर भी असर पड़ता है। पिछले साल यह साफ हो गया था कि डॉलर में कर्ज जारी करने को लेकर अहम प्रतिरोध हो रहा है, इसलिए हम घरेलू वित्तीय बाजारों पर निर्भर हैं। घरेलू वित्तीय बाजारों की घाटे की भरपाई करने की क्षमता उनके आकार पर निर्भर करती है। वहीं घरेलू वित्तीय बाजारों का आकार परिवारों की वित्तीय बचत और विदेश से धन की आवक पर निर्भर करती है। अधिक विनिवेश प्राप्तियों का मतलब है कि इक्विटी बाजार के भागीदारों के पास जुटाने के लिए घरेलू वित्तीय बचतें कम होंगी। घरेलू वित्तीय बचतें जीडीपी की 10 फीसदी हैं।

परंपरागत रूप से बॉन्ड बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों के कारण निजी क्षेत्र पैसा नहीं जुटा पाता है। बहुत से लोगों के विचार से इक्विटी बाजारों में विदेशी भागीदारी ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इसलिए वित्त के कोष को बढ़ाने का एकमात्र तरीका यह बचता है कि डेट बाजार में विदेशी भागीदारी बढ़ाई जाए। असल में सरकार के पास अन्य विकल्प बहुत कम हैं। इस तरह संकट का तात्कालिक असर इस तरह भी दिख रहा है कि सरकार अपने घाटे की भरपाई के लिए विदेशी कर्ज की आवक के रास्ते खोल रही है।

इसके बाद दो अहम सवाल बचते हैं। पहला, अगर ऐसे धन की आवक होती है तो रुपये के मूल्य और सुधार के एकमात्र टिकाऊ रास्ते निर्यात में वृद्धि पर क्या असर पड़ेगा? दूसरा क्या इस धन की भारत में आवक को बढ़ाने के प्रयासों में सरकारी खर्च के चैनल पर प्रभावी ध्यान दिया गया है?

सेना के लिए रकम जुटाने के वास्ते हटकर सोचने की जरूरत

दोधारी तलवार

अजय शुक्ला

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में इस बात का खुलासा नहीं किया कि वह रक्षा क्षेत्र को कितना आवंटित कर रही हैं। उसी समय यह साफ हो गया था कि इसमें मामूली बढ़त होने जा रही है। जब आंकड़े सामने आए तो यह आशंका सही साबित हुई। रक्षा खर्च में 5 फीसदी की मामूली बढ़ोतरी की गई है जो महंगाई की भरपाई करने के लिए भी काफी नहीं है। सरकार ने साफ कर दिया है कि उसकी प्राथमिकता शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के विकास पर खर्च बढ़ाना है। कुल बजट आवंटन में सेना का हिस्सा लगातार कम हो रहा है। 2018-19 में यह 17.4 फीसदी और 2019-20 में 16.6 फीसदी था और 2020-21 में 15.5 फीसदी रह गया है।

जब देश में बच्चे कुपोषण का शिकार हैं, आम जनता चिकित्सा सुविधाओं से वंचित है और युवाओं के पास रोजगार पाने के लिए पर्याप्त शिक्षा नहीं है, तो रक्षा पर ज्यादा खर्च की दलील देना मुश्किल है। हमारे पास सैन्य महाशक्ति बनने के लिए आर्थिक संसाधनों की कमी है, इसलिए हम बेलगाम राष्ट्रवाद का झंडा उठाए नहीं फिर सकते हैं। हमें चीन से अपनी तुलना करने के बजाय यह सोचना चाहिए कि हम रक्षा पर कितना खर्च करने में सक्षम हैं। उसी के हिसाब से हमें अपनी विदेश और आंतरिक नीति बनानी चाहिए। सरकार के बजट में अब भी रक्षा का हिस्सा सबसे बड़ा है, इसलिए हमें इसके बेहतर उपयोग के लिए व्यापक चर्चा करनी चाहिए।

बजट का सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा यह था कि सेना के लिए वेतन (111,294 करोड़ रुपये) से ज्यादा पेंशन (113,278 करोड़ रुपये) की राशि आवंटित की गई है। यानी सरकार अपने मौजूदा सैनिकों की तुलना में पूर्व सैनिकों पर ज्यादा खर्च करेगी। इस तर्क का मतलब यह नहीं है कि पूर्व सैनिकों को नजरअंदाज किया जाए जिन्होंने अपना जीवन का बहुमूल्य समय मातृभूमि की सेवा में खपाया है। बल्कि यह खुद को याद दिलाने का समय है कि वे सभी वर्ष अर्थव्यवस्था और सेना के लिए नुकसान के रहे हैं। कई विशेषज्ञ समितियों ने अपनी रिपोर्ट में शॉर्ट सर्विस व्यवस्था से इसका समाधान किया जा सकता है। इसके तहत सैनिक तीन से चार साल के लिए अपनी सेवा देते हैं और फिर पेंशन के बिना सेवानिवृत्त होकर श्रम बल के रूप में अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं। लेकिन निहित स्वार्थों के कारण यह व्यवस्था कभी नहीं अपनाई गई।

अमूमन, एक के बाद एक सभी सरकारों को भारी-भरकम पेंशन बिल का सामना करना पड़ा है और उन्होंने इसे रक्षा बजट से अलग दिखाने की कोशिश की है। बजट के बाद रक्षा मंत्रालय ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि रक्षा के लिए 337,553 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं जिसमें रक्षा पेंशन शामिल नहीं है। शाब्दिक रूप से यह सही है, लेकिन यह पृथक्करण इस बात को समझने की अनिच्छा को दिखाता है कि पेंशन बजट जनरलों द्वारा बनाई गई नीतियों का पालन करता है। सैन्य बलों के नए प्रमुख (सीडीएस) को इस पर ध्यान देना चाहिए। सेना प्रमुख के रूप में उन्होंने सेना में सुधार के लिए कुछ कदम उठाए थे।

इन सुधारों में इस बात को भी शामिल किया जाना चाहिए कि रसद और रखरखाव के कामों को असैन्य क्षेत्र के हवाले किया जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि असैन्य क्षेत्र में इसकी लागत कम है। इससे सैन्य ठिकानों के आसपास स्थानीय अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी और पूर्व सैनिकों को रोजगार मिलेगा। उदाहरण के लिए ब्रिटेन में शाही वायुसेना के अधिकांश विमानों का रखरखाव और मरम्मत अनुबंध पर रखे गए आरएएफ के पूर्व सैनिक करते हैं।

बजट संबंधी अन्य तत्काल जरूरत तीनों सेनाओं के बीच राशि का सुसंगत वितरण है। एक विश्लेषण के मुताबिक साल दर साल थलसेना, नौसेना और वायुसेना को मोटे तौर पर रक्षा बजट में समान हिस्सा मिलता रहा है और अपनी भूमिका, प्रौद्योगिकी या माहौल में बदलाव के बावजूद वे उसी मुताबिक खर्च करते रहे हैं। हर साल थलसेना को रक्षा बजट की लगभग दो-तिहाई राशि मिलती है और वह इसमें से करीब तीन-चौथाई हिस्सा वेतन और पेंशन पर खर्च करती है। इससे उसके पास आधुनिक हथियारों की खरीद के लिए करीब 10 फीसदी राशि ही बच जाती है। दूसरी नौसेना और वायुसेना अपने कुल आवंटन का करीब आधा हिस्सा नए हथियार खरीदने में पर खर्च करती हैं क्योंकि उनके कर्मचारियों की संख्या कम है।

समस्या यह है कि यह वितरण लक्षित प्राथमिकताओं के आधार पर नहीं होता है जहां जनरल, एडमिरल और एयर मार्शल मिलकर अपनी जरूरत की परिचालन क्षमताओं के बारे में फैसला करते हैं। यह प्रक्रिया आसान नहीं है। सभी इस बात पर सहमत होंगे कि हमें सीमा पार स्थित आतंकी ठिकानों पर हमलों के लिए तैयार रहने की जरूरत है लेकिन इस बात पर गंभीर मतभेद हैं कि ऐसा कैसे किया जाए। वायुसेना के विमानों से या सतह से सतह पर मार करने वाले प्रक्षेपास्त्रों से? या फिर इस काम के लिए सेना के विशेष बलों का गठन किया जाना चाहिए? अगर हवाई हमलों पर सहमति बनती है तो लड़ाकू विमानों और प्रक्षेपास्त्रों को खरीदने के लिए अतिरिक्त रकम मुहैया कराई जानी चाहिए। अगर विशेष बलों को यह जिम्मेदारी दी जाती है तो थलसेना को विशेष बल कमान बनाने के लिए मदद दी जानी चाहिए। तीनों सेनाएं पिछले वर्ष आवंटित राशि के आधार पर अपने वित्तीय अनुमान तैयार करती हैं। रक्षा मंत्रालय उनमें औसतन 30 से 35 फीसदी की कटौती करता है। आवंटन से पहले वित्त मंत्रालय इनमें और कटौती करता है। इसका नतीजा यह होता है कि हर साल सेना के तीनों अंगों को पिछले साल की तुलना में थोड़ा अधिक आवंटन किया जाता है लेकिन उसका अनुपात कमोबेश समान होता है। सेना के आधुनिकीकरण के लिए रकम मुहैया कराने के वास्ते हटकर सोचने की जरूरत है। सेना की दीर्घकालिक योजना के मुताबिक आधुनिक हथियार खरीदने के लिए रक्षा बजट में आवंटित राशि के इतर 13 लाख करोड़ रुपये की जरूरत होगी।

कानाफूसी

पशु-पक्षियों का आतंक

राष्ट्रीय पक्षी मोर और गोवा के राजकीय पशु गौर को गोवा में फसलों के नुकसान के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने सोमवार को गोवा विधानसभा को बताया कि मोर और बंदर प्रदेश में बागवानी के लिए बड़ी मुसीबत बनकर उभरे हैं। कुछ वर्ष पहले तो प्रदेश के कृषि मंत्रालय ने मोर, बंदरों और राजकीय पशु गौर को परेशानी खड़ी करने वाले जीवों की सूची में डाल दिया था। विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत एक लिखित प्रतिक्रिया में सावंत ने बताया कि सरकार ने नुकसान को कम करने के लिए क्या उपाय अपनाए हैं। उन्होंने कहा कि गोवा के वन क्षेत्रों में तथा अन्य स्थानों पर खाली पड़ी जमीन पर स्थानीय फलदार प्रजातियों के पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा वन्य जीवों के लिए जंगलों के भीतर पानी के गड्ढे तैयार किए जा रहे हैं ताकि वे पानी पी सकें।

महात्मा बनाम बेन किंग्सले

मध्य प्रदेश में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा की स्थापना के बाद विवाद उत्पन्न हो गया। कारण? यह प्रतिमा राष्ट्रपिता की कम और ब्रिटिश अभिनेता बेन किंग्सले की अधिक नजर आ रही है। किंग्सले ने सन 1982 में बनी महात्मा गांधी की बायोपिक में काम किया था जिसका निर्देशन रिचर्ड एटनबरो ने किया था। यह प्रतिमा प्रदेश के रीवा जिले के एक महाविद्यालय में स्थापित की गई। विद्यार्थियों ने यह कहकर इसका विरोध करना शुरू कर दिया कि यह गांधी जी से तनिक भी मेल नहीं खाती। कॉलेज ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि इसका चयन राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग ने किया था। बहरहाल आईफा अवार्ड 2020 के भोपाल और इंदौर में आयोजित होने की घोषणा के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता शिवराज सिंह चौहान ने चुटकी लेते हुए कहा कि मुख्यमंत्री कमल नाथ और कांग्रेस के उनके सहयोगी फिल्मों से इतने प्रभावित हो गए हैं कि वे यह तक भूल गए कि महात्मा गांधी दिखते कैसे थे।

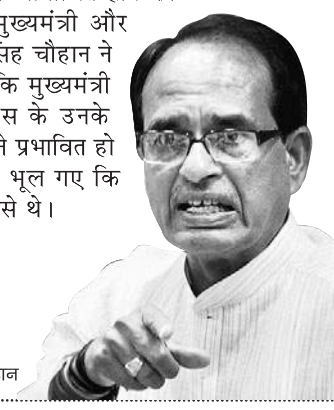

शिवराज सिंह चौहान

आपका पक्ष

कैसे दूर होगी देश की आर्थिक मंदी

हाल ही में 2019-20 की आर्थिक समीक्षा में कहा गया कि देश की आर्थिक मंदी जल्द ही खत्म हो सकती है। मोदी सरकार को न तो आर्थिक समीक्षा के आधार पर और न ही किसी संस्था के आर्थिक आंकड़ों से देश की आर्थिक व्यवस्था के सुधार पर अपनी पीठ खुद थपथपानी चाहिए, क्योंकि जो भी सर्वेक्षण और आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, वे गांवों या देश के छोटे-छोटे शहरों की हकीकत बयां नहीं करते हैं, जबकि भारत गांवों में ही बसता है। महात्मा गांधी ने भी आर्थिक समानता लाने की कोशिश की थी। गांधीजी कहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति के पास इतना धन तो हो जिससे वह अपनी मूलभूत ज़रूरतें पूरी कर सके। जब तक देश में गरीबी, बेरोजगारी जैसी समस्याएं खत्म नहीं होतीं, तब तक अर्थव्यवस्था के आंकड़ों का मजबूत होना कोई मायने नहीं रखता है। वर्ष 1951-52 में जब पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी, तब विनोबा भावे ने कहा था कि सरकार की सभी राष्ट्रीय योजनाओं का मकसद रोजगार बढ़ाना ही होना चाहिए। बेरोजगारी से निपटने के लिए सरकार को योजनाएं ही नहीं, बल्कि उसे अमल में लाने के लिए गंभीरता भी दिखानी चाहिए। सरकार को ऐसी कोई योजना या नीति बनाने से परहेज करना चाहिए, जिससे किसी भी उद्योग-धंधे पर नकारात्मक असर पड़े। उद्योग-धंधों के सुदृढ़ होने से आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ होने के साथ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

सरकार को बेरोजगारी दूर करने के लिए योजनाओं के साथ इसके क्रियान्वयन पर ध्यान देना होगा

मंदी से उबारने पर ध्यान दे सरकार

देश के लोग सरकार से विकास चाहते हैं। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो वर्षों से नहीं हुए। मगर इस समय जो मंदी है, उससे हर कोई परेशान है। केंद्र सरकार को इसपर विशेष ध्यान देना चाहिए। वर्तमान में उद्योग एवं व्यापार बुरे दौर से गुजर रहे हैं। पहले ही देश में बेरोजगारी का संकट था, लेकिन अब कर्मचारियों की छंटनी से स्थिति बदतर होती जा रही है। रोजगार देने वाले निजी क्षेत्र बहुत ही खराब दौर से गुजर रहे हैं। अगर ऐसे ही हालात बने रहे तो पांच अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था दिवा स्वप्न बनकर रह जाएगी। ऐसे में आवश्यकता इस बात की है कि रोजगार और उत्पादन बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार तुरंत प्रभावी पहलकदमी करे।

भूपेंद्र सिंह रंगा, पानीपत

कोरोनावायरस से बचाव ही उपचार है

चीन में जब से कोरोनावायरस के मामले सामने आए हैं दुनिया भर के बाकी देश अपने नागरिकों को वापस बुला रहे हैं। ऐसे में यदि आप विदेश यात्रा करने वाले हैं तो फिलहाल इसे टाल देना ही बुद्धिमानी होगी। क्योंकि कहा जा रहा है कि जानवरों और समुद्री जीवों में पाया जाना वाला यह वायरस अब मानव से मानव में फैल रहा है। चीन से बाहर निकल रहे लोगों के साथ यात्रा करने पर इससे संक्रमित होने का खतरा अधिक है। इसके अलावा भीड़ वाले इलाकों से दूर रहने की हिदायत दी जा रही है, विशेषकर जहां मांस या मछली का बाजार लगा हो। यदि मांसाहार करते हैं तो उसे पूरी तरह से पका कर खाएं और हो सके तो मछली तथा मांस का सेवन कुछ दिनों के लिए रोक दें। अधपका मांस तो बिल्कुल भी न खाएं।

विनोद प्रजापति, जयपुर

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।

जिंस एक्सचेंज 'अनुबंधों' की करें समीक्षा

एक्सचेंजों को हर साल 30 जून तक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को देनी होगी रिपोर्ट

दिलीप कुमार झा
मुंबई, 4 फरवरी

बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने जिंस एक्सचेंजों को सभी जिंस डेरिवेटिव अनुबंधों के प्रदर्शन की सालाना आधार पर समीक्षा करने और उसे हर साल 30 जून तक रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। एक्सचेंजों को इन ब्योरों को सार्वजनिक भी करना होगा। नियामक का यह कदम अत्यंत महत्त्वपूर्ण है क्योंकि इससे सभी अनुबंधों की उपयोगिता, हेजिंग और अन्य अहम पहलू सामने आएंगे।

सेबी ने 4 फरवरी को भेजे परिपत्र में जिंस एक्सचेंजों से कहा है कि वे सभी जिंसों की बैलेंस शीट तैयार करें, जिसमें मात्रा, ओपन इंटरेस्ट और जिंस एक्सचेंजों पर कारोबार जैसे ब्योरे शामिल हों। इसके अलावा एक्सचेंजों को उन जिंसों के 10 सबसे बड़े उत्पादक और उपभोक्ता देशों की जानकारी देनी होगी। वैश्विक बैलेंस शीट के अलावा नियामक ने एक्सचेंजों से घरेलू नजरिये से प्रत्येक जिंस का ब्योरा देने और स्थानीय बाजार में उत्पादन एवं खपत की जानकारी देने को कहा है।

सभी जिंसों के वैश्विक और घरेलू आंकड़े प्रकाशित होने से हेजर्स और अन्य भागीदारों को बाजारों का रुझान समझने और उसके मुताबिक पोजिशन लेने में मदद मिलेगी। इससे एक्सचेंजों के भागीदारों को अत्यधिक उतार-चढ़ाव की स्थिति में डिफॉल्ट से बचने में मदद मिलेगी।

कृषि जिंसों में वायदा कारोबार की सुविधा मुहैया कराने वाले देश के सबसे बड़े एक्सचेंज नैशनल कमोडिटी ऐंड डेरिवेटिव्ज एक्सचेंज लिमिटेड (एनसीडीईएक्स) के प्रमुख (कृषि कारोबार) कपिल देव ने कहा, 'कृषि जिंसों के डेरिवेटिव बाजार का मकसद ही हेजिंग है, इसलिए इस बाजार को समझना बहुत जरूरी है। जिंसों और भागीदारों के ब्योरों से कारोबारियों को राहत मिलेगी। इससे कारोबारियों का भरोसा बढ़ेगा और पूरा जिंस तंत्र मजबूत होगा।'

सेबी ने दिए एक्सचेंजों को नए निर्देश

- हेजर्स और अन्य भागीदारों को बाजारों का रुझान समझने व उसके मुताबिक पोजिशन लेने में मदद मिलेगी
- एक्सचेंज भागीदारों को अत्यधिक उतार-चढ़ाव की स्थिति में डिफॉल्ट से बचने में मदद मिलेगी

इसके अलावा नियामक ने जिंस एक्सचेंजों को भागीदारों के प्रकार की जानकारियां देने को कहा है। इसका मतलब है कि जिंस एक्सचेंजों को किसानों, हेजर्स, उपयोगकर्ताओं और किसानों के उत्पादक संगठनों (एफपीओ) जैसे भागीदारों के ब्योरे साझा करने होंगे।

सेबी ने आज जारी परिपत्र में कहा, 'ऐसे अनुबंधों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने ऐसा खाका तैयार करना जरूरी है, जो न केवल महज डिलिवरी और कारोबारी मात्रा पर आधारित हो बल्कि व्यापक आनुभाविक मूल्यांकन पर आधारित हो।' सेबी ने एक्सचेंजों से कहा है कि वे इन ब्योरों के बारे में अपनी उत्पाद सलाहकार समिति से चर्चा करें और फिर उनका अपनी वेबसाइटों पर प्रकाशन करें।

कमोडिटी पार्टिसिपेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीपीएआई) के अध्यक्ष नरिंदर वाधवा ने कहा, 'इससे जिंस एक्सचेंजों को अपना डेटा सेबी के साथ साझा करना होगा। यह अत्यंत जरूरी था और इससे सिस्टम में ज्यादा पारदर्शिता आएगी।'

सेबी ने यह भी कहा कि यह नियम 1 अप्रैल 2020 से लागू हो जाएगा और वित्त वर्ष 2020 में सभी अनुबंधों के प्रदर्शन पर लागू होगा। इस परिपत्र से जिंस एक्सचेंजों को भारत में पाई जाने वाली जिंसों के जीवनकाल एवं किस्मों और संबंधित जिंस के हाजिर बाजार में कारोबार को नियंत्रित करने वाली नीति में प्रमुख बदलावों का ब्योरा देना होगा। इसके अलावा सेबी ने एक्सचेंजों को निर्देश दिया है कि वे जिंस के भू-राजनीतिक मुद्दों और उसके भारत पर असर के बारे में ब्योरे मुहैया कराएं।

आनंद राठी शेयर्स ऐंड स्टोकब्रोकर्स लिमिटेड के निदेशक (जिंस एवं मुद्रा) नवीन माथुर ने कहा, 'इस कदम का मकसद हाजिर बाजार और वायदा बाजार में तालमेल कायम करना है।' देव के मुताबिक वैश्विक स्तर पर एक्सचेंजों में उत्पादन के मुकाबले ओपन इंटरेस्ट आम तौर पर 20 से 30 फीसदी होता है। उन्होंने कहा कि ओपन इंटरेस्ट की तुलना में लेनदेन करीब 30 फीसदी होता है।

देव ने कहा, 'कृषि जिंसों में भारत ओपन इंटरेस्ट के मुकाबले लेनदेन में समान स्तर पर है। ओपन इंटरेस्ट अधिक है और कारोबारी मात्रा अधिक है क्योंकि आर्बिट्रेजर्स समेत डे-ट्रेडर और अन्य भागीदारों की भागीदारी अधिक है। इसलिए इन आंकड़ों के प्रकाशन से निश्चित रूप से भारत में जिंस कारोबार को लेकर सकारात्मक नजरिया मिलेगा।'

जनवरी में देश का स्वर्ण आयात 48 प्रतिशत फिसला

रॉयटर्स
नई दिल्ली/मुंबई, 4 फरवरी

पिछले साल के मुकाबले जनवरी में देश का स्वर्ण आयात 48 प्रतिशत फिसलकर चार महीने के निचले स्तर पर आ गया है। रिकॉर्ड शीर्ष स्तर पर पहुंचे स्थानीय दामों ने खरीदारों को खरीद में कमी करने के लिए प्रेरित किया जिससे आयात में कमी आई। मंगलवार को एक सरकारी सूत्र ने यह जानकारी दी। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े स्वर्ण खरीदार भारत द्वारा की गई इस कीमती धातु की कम खरीद से वैश्विक दामों पर दबाव बन सकता है जो करीब सात साल के शीर्ष स्तर पर चल रहे हैं। हालांकि इससे भारत को व्यापार घाटा कम करने और रुपये को समर्थन मिलने में मदद मिलेगी।

सूत्र ने बताया कि भारत ने जनवरी में 36.26 टन सोने का आयात किया, जबकि एक साल पहले 69.51 टन सोने का आयात किया गया था। मूल्य के हिसाब से जनवरी में कुल आयात 1.58 अरब डॉलर रहा, जो पिछले साल के 2.31 अरब डॉलर से कम है।

एक निजी बैंक में सराफा अनुभाग के प्रमुख ने कहा कि उपभोक्ता अधिक दामों से तालमेल बैठाने के लिए जूझ रहे हैं। दाम तेजी से काफी ज्यादा बढ़े हैं। दामों में कमी आने की उम्मीद से कई संभावित उपभोक्ता अपनी खरीद टाल रहे हैं।

वर्ष 2019 में करीब एक तिमाही बढ़ने के बाद देश में सोने का वायदा भाव जनवरी में प्रति 10 ग्राम 41,293 रुपये के रिकॉर्ड शीर्ष स्तर तक पहुंच गया है। कमजोर मांग ने जनवरी में कारोबारियों को सामान्य घरेलू दामों के मुकाबले प्रति औंस 13 डॉलर की छूट देने के लिए विवश किया है जो करीब तीन महीने के शीर्ष स्तर पर चल रहे हैं। घरेलू दामों में 12.5 प्रतिशत आयात शुल्क और तीन प्रतिशत बिक्री कर शामिल रहता है।

मुंबई स्थित सोने के थोक विक्रेता चेनाजी नरसिंहजी के मालिक अशोक जैन ने कहा कि जब तक दाम मौजूदा स्तर से काफी ज्यादा कम नहीं हो जाते, तब तक निकट भविष्य में मांग में सुधार होने की उम्मीद नहीं है। जैन ने कहा कि खुदरा मांग नरम है। यहां तक कि शादी-विवाह के लिए भी लोग खरीद में कटौती कर रहे हैं।

- जनवरी में सोने का 36.26 टन आयात हुआ जो एक साल पहले 69.51 टन था
- मूल्य के हिसाब से जनवरी में कुल आयात 1.58 अरब डॉलर रहा जो पिछले साल के 2.31 अरब डॉलर कम है

भारत में शादी-विवाह सोने की खरीद के सबसे बड़े संचालकों में से एक रहता है क्योंकि गहनों के रूप में सराफा लोकप्रिय उपहार होता है। विश्व स्वर्ण परिषद (डब्ल्यूजीसी) ने गत सप्ताह कहा था कि पिछले साल के मुकाबले वर्ष 2019 में भारत का स्वर्ण उपभोग नौ प्रतिशत गिरकर 690.4 टन रह गया जो वर्ष 2016 के बाद का निम्नतम स्तर है। स्वर्ण आयातक बैंक के मुंबई स्थित एक कारोबारी ने कहा कि फरवरी में देश का स्वर्ण आयात गिरकर 40 से कम रह सकता है क्योंकि दाम अब भी अधिक हैं।

अंतरराष्ट्रीय और घरेलू भाव

As on Feb 4	International Price	International %Chg#	Domestic Price	Domestic %Chg#
METALS ($/tonne)				
Aluminium	1,694.5	-5.2	2,020.5	6.7
Copper	5,595.0	-4.3	6,300.0	3.0
Nickel	12,750.0	-23.2	13,680.4	-21.3
Lead	1,879.0	-13.6	2,118.7	-2.0
Tin	16,350.0	-0.6	17,328.5	-1.1
Zinc	2,200.0	-14.9	2,483.5	-9.4
Gold ($/ounce)	1,568.4*	3.9	1,765.0	3.9
Silver ($/ounce)	17.7*	-1.9	20.1	-2.2
ENERGY				
Crude Oil ($/bbl)	53.9*	-13.6	58.0	-5.6
Natural Gas ($/mmBtu)	1.8*	-35.1	1.8	-35.0
AGRI COMMODITIES ($/tonne)				
Wheat	194.6	8.9	291.1	-4.1
Maize	186.4*	8.1	268.6	-4.5
Sugar	418.1*	21.5	490.0	-0.7
Palm oil	687.5	17.5	1,129.5	18.4
Rubber	1,370.4*	-1.9	1,866.1	5.7
Coffee Robusta	1,309.0*	2.5	1,810.0	-5.5
Cotton	1,496.1	6.6	1,587.2	-2.0

* As on Feb 4, 20 1800 hrs IST, # Change Over 3 Months, Conversion rate 1 USD = 71.3& 1 Ounce = 31.1032316 grams.

Notes:
1) International metals, Indian basket crude, Malaysia Palm oil, Wheat LIFFE and Coffee Karnataka robusta pertains to previous days price. 2) International metal are LME Spot prices and domestic metal are Mumbai local spot prices except for Steel. 3) International Crude oil is Brent crude and Domestic Crude oil is Indian basket. 4) International Natural gas is Nymex near month future & domestic natural gas is MCX near month futures. 5) International Wheat, White sugar & Coffee Robusta are LIFF E future prices of near month contract. 6) International Maize is MATIF near month future, Rubber is Tokyo-TOCOM near month future and Palm oil is Malaysia FOB spot price. 7) Domestic Wheat & Maize are NCDEX future prices of near month contract, Palm oil & Rubber are NCDEX spot prices. 8) Domestic Coffee is Karnataka robusta and Sugar is M30 Mumbai local spot price. 9) International cotton is Cotton no.2-NYBOT near month future & domestic cotton is MCX Future prices near month tures.

Bloomberg chartMaker | Compiled by BS Research Bureau

एमसीएक्स

Name	Tovr (₹ Cr)	OI(000)
Agri commodity		
Cotton	64.5	35057
Oil and Oilseeds	306.7	74271
Spices	0.3	9
Metal(Feb 03)		
Metal- non ferrous	4681.3	48848
Metal- precious	11436.4	380
Oil and gas(Feb 03)		
Gas	2122.7	53271
Oil	20766.1	3218

एनसीडीईएक्स

Name	Tovr (₹ Cr)	OI(000)
Agri commodity		
Cotton	171.8	136230
Grains	185.9	97825
Oil and Oilseeds	645.7	461920
Others	102.3	65690
Pulses	71.5	37475
Spices	47.4	21602

एमसीएक्स बढ़ा/घटा

Name (Maturity)	Close	Day*
Gainers (* % Change)		
Crude Palm Oil (Feb 28)	745.8	2.6
Cotton (Feb 28)	19230.0	0.7
Kapas (Apr 30)	1069.0	0.5
Losers (* % Change)		
Cardamom (Feb 14)	3608.3	-2.7
Silver Micro (Feb 28)	45900.0	-2.6
Silver Mini (Feb 28)	45908.0	-2.6
Silver (Mar 05)	45890.0	-2.6
Aluminium Mini (Feb 28)	135.8	-2.2
Zinc Mini (Feb 28)	170.4	-2.1
Natural Gas (Feb 25)	131.1	-2.1
Lead Mini (Feb 28)	144.8	-2.1
Zinc (May 29)	173.8	-1.8

एनसीडीईएक्स बढ़ा/घटा

Name (Maturity)	Close	Day*
Gainers (* % Change)		
Turmeric Nizamabad (Mar 20)	6018.0	1.7
Coriander-Kota (Apr 20)	6378.0	1.7
Ref Soy Oil-IDR-2016 (Feb 20)	846.6	1.5
Mustard Seed Rape Oil (Feb 20)	4107.0	0.6
Shankar Kapas-Rajkot (Apr 30)	1069.0	0.6
Guar Seed 10 (Feb 20)	3876.0	0.5
GuarGum 5T-Jodhpur (Feb 20)	6884.0	0.3
Soyabean Indore (Feb 20)	4062.0	0.2
CottonSeed Oil-Akola (Feb 20)	1757.0	0.2
Losers (* % Change)		
Jeera Unjha (Mar 20)	13775.0	-1.1
CastorSeed New-Disa (Feb 20)	3856.0	-0.9
Chana-Bikaner (Mar 20)	3971.0	-0.7

एमसीएक्स बढ़त/छूट

Name (Maturity)	Futures	Prem/Dis
Premium over spot price (In %)		
Kapas Surendranagar (Apr 30)	1069.0	5.6
Cotton-Rajkot (Feb 28)	19230.0	1.5
Gold Ahm (Feb 05)	40661.0	0.5
Discount over spot price(In %)		
Menthol Oil Chandaus (Feb 28)	1181.0	-10.3
Lead Min Mumbai (Feb 28)	144.8	-6.0
Lead Mum (May 29)	146.6	-4.8
Zinc Mini Mumbai (Feb 28)	170.4	-3.9
Cardamom Vandanmedu (Feb 14)	3608.3	-3.7
Alumini-Mumbai (Feb 28)	135.8	-3.2
Nickel Mumbai (Feb 28)	937.8	-3.1
Zinc Mumbai (May 29)	173.8	-2.0
Copper Mum (Feb 28)	421.8	-1.8

एनसीडीईएक्स बढ़त/छूट

Name (Maturity)	Futures	Prem/Dis
Premium over spot price (In %)		
Paddy-Basmati-Karnal (Feb 20)	3184.0	1.9
Turmeric Nizamabad (Mar 20)	6018.0	1.9
Maize-Sangli (Feb 20)	1914.0	0.6
Bajra-Jaipur (Feb 20)	1892.0	0.6
29 mm Cotton-Rajkot (Feb 20)	18870.0	0.5
Moong-Merta City (Feb 20)	7705.0	0.4
Discount over spot price (In %)		
Barley Jaipur (Apr 20)	1733.5	-19.4
Jeera Unjha (Mar 20)	13775.0	-6.0
Soy Bean Indore (Feb 20)	4062.0	-2.1
Guar Gum 5 MT-Jodhpu (Feb 20)	6884.0	-1.6
Coriander-Kota (Apr 20)	6378.0	-1.4

कल का हाजिर भाव

औद्योगिक

Metals	Mumbai
Aluminium utensil scrap /kg	106......(106)
Aluminium ingots /kg	144......(144)
Brass sheet cutting /kg	320......(325)
Brass utensil scraps/kg	305......(305)
Copper heavy scrap /kg	416......(415)
Copper utensil scraps/kg	390......(391)
Copper wire bar /kg	449......(449)
Lead ingots /kg	151......(154)
Nickel Cathodes /kg	975......(960)
Tin slabs /kg	1235......(1225)
Zinc slabs /kg	177......(181)

Source:Bombay Metal Exchange

Cotton	Mumbai
Bengal Deshi /Qtl	10236......(10236)
DCH - 32 /Qtl	11248......(11220)
Jaydhar /Qtl	9758......(9758)
Shankar- 6 /Qtl	11023......(10995)

Source:Cotton Association of India

Oil	Mumbai
Castor FSG /10kg	837......(845)
Castor Comm /10kg	827......(835)
Ricebran oil/10kg	-......(820)
Groundnut oil /10kg	1140......(1140)
Linseed oil /10kg	-......(935)
Karanji /10kg	-......(800)
Palm oil /10kg	840......(840)
Sunflower exp ref /10kg	870......(880)
Sunflower oil exp /10kg	830......(840)
Soyabean ref / 10kg	855......(860)

Source:Bombay Commodity Exchange

सॉफ्ट

Sugar	Mumbai
Mumbai M-30 /Qtl	3382-3602 ......(3382-3595)

Source:Bombay Sugar Merchants Association

ऊर्जा

Crude Brent-$/Barrel	
NYSE Crude	50.74......(50.11)
Brent Crude (UK)	53.65......(53.24)
Brent Crude (WTI)	50.11......(50.11)
NYSE Natural Gas-$/Mmbtu	1.83......(1.82)
Furnace/ 180 Cst &/bbl	287.48......(269.56)
Naptha spot /Rs/MT	45170......(45170)
LSHS spot/ M.T.	36150......(36150)
Furnace Oil spot/ K.L.	33950......(33950)

Source:Petroleum Bazaar.com

सर्राफा

Gold	Mumbai
Standard (99.50 Purity) /10 gms	40443......(40654)
Pure (99.90 Purity) /10 gms	40606......(40817)
Silver.999/ kg	46010......(46240)

Source:India Bullion & Jewellers Association

@SPOT PRICE(MCX, NCDEX & ICEX)

Commodity	Unit	PClose	Price (₹.) Close
29 mm Cotton-Rajkot (N)	1 B	18818.40	18777.35
Alumini-Mumbai (M)	1 K	142.20	140.35
Bajra-Delhi (N)	1 Q	1915.00	1905.00
Bajra-Jaipur (N)	1 Q	1886.75	1881.10
Barley Jaipur (N)	1 Q	2150.45	2150.00
Cardamom-Vand. (I)	1 K	3783.00	3717.00
Castor Seed Disa (N)	1 Q	4058.35	4020.00
Castor Seed-Kadi (N)	X	4060.00	3995.00
Chana Bikaner (N)	1 Q	4078.50	4075.20
Chana Delhi (N)	1 Q	4300.00	4293.15
Chana-Akola (N)	X	4050.00	4015.00
Coriander-Gondal (N)	X	6289.00	6250.00
Coriander-Jaipur (N)	X	6366.65	6400.00
Coriander-Kota (N)	1 Q	6507.45	6468.80
Cotton Seed Oilck Ak (N)	1 Q	1850.75	1821.25
Cotton Seed Oilck Ka (N)	1 Q	1917.45	1908.40
Cotton-Kadi (N)	1 B	18886.25	18883.60
CPO-Kandla (M)	10 K	744.30	751.00
Crude Palm Oil Kandl (N)	10 K	712.80	716.70
Crude Palm Oil-KAKIN (N)	10 K	725.00	722.50
Diamond 0.3 - Surat (I)	1 CT	910.30	903.30
Diamond 0.5-Surat (I)	1 CT	1553.55	1549.30
Diamond 1-Surat (I)	1 CT	3466.15	3449.20
Gold Ahm (M)	10 G	40703.00	40471.00
Gold Guinea-Ahmedaba (M)	8 G	32693.00	32507.00
Gold Petal-Mumbai (M)	1 G	4083.00	4066.00
Guar Gum 5 MT-Jodhpu (N)	X	7000.00	6999.15
Guar Seed 10 MT-Jodh (N)	1 Q	3903.35	3900.45
Guarseed-Jodhpur (I)	1 Q	3913.00	3840.00
Gur Muzaffar Nagar (N)	40 K	1067.50	1078.10
Isabgulseed-Unjha (I)	1 K	104.25	104.75
Jeera Jodhpur-Jodhpu (N)	X	15400.00	15200.00
Jeera Unjha (N)	1 Q	14725.00	14650.00
Kachi Ghani Must Oil (N)	10 K	854.75	850.00
Kapas Kadi-Kadi (N)	X	1022.60	1014.20
Kapas-Rajkot (N)	X	1017.20	1009.85
Lead Mum (M)	1 K	155.10	154.00
Maize Kharif-Nizamab (N)	X	1899.40	1886.25
Maize Rabi-Gulabbagh (N)	1	2200.00	2192.10
Maize-Erode (N)	X	1900.00	1848.65
Maize-Feed/Ind- Gula (N)	1 Q	2200.00	2192.10
Maize-Feed/Ind-Delhi (N)	1 Q	2012.50	2010.00
Maize-Sangli (N)	X	1908.35	1902.00
Masoor Grain Bold In (N)	1 Q	4750.00	4700.00
Moong-Merta City (N)	1 Q	7685.00	7677.50
Mustardseed Alwar (N)	20 K	4334.00	4334.00
Nickel Mumbai (M)	1 K	963.00	968.00
Paddy-Basmati-Karnal (N)	X	3175.00	3125.00
Paddy-Basmati-Karnal (I)	1 Q	3190.00	3175.00
Pepper-Ernakulam (I)	1 K	330.00	330.00
Pepper-Kochi (N)	1 Q	33150.00	33400.00
R M Oil-Sriganganaga (N)	X	830.00	837.50
Rape mustards-Patan (I)	20 K	768.00	750.00
Rapeseed Must.Seed (N)	X	1912.50	1913.75
Raw Jute-Kolkatta (N)	X	5324.00	5347.40
RBD Palm Olein Kakin (N)	10 K	805.00	805.00
Ref Soya Oil Indore (N)	10 K	867.15	867.20
Ref Soya Oil Mum (N)	10 K	864.90	865.05
Ref Soya Oil Nagpur (N)	10 K	870.50	869.25
Rubber-Kochi (N)	1 Q	13200.00	13300.00
Rubber-Kochi/Ernak. (I)	1 Q	13250.00	13217.00
Silver M-Ahemdabad (M)	1 K	46233.00	45996.00
Soy Bean Indore (N)	1 Q	4173.00	4148.00
Soy Bean Kota (N)	1 Q	4090.50	4090.50
Soy Bean Nagpur (N)	1 Q	4242.00	4242.00
Soy Bean-Akola (N)	X	4217.00	4200.00
Soymeal Indore (N)	1 T	33500.00	33375.00
Soyoil-Indore (I)	10 K	870.00	866.00
Steel Long-Ghaziabad (I)	1 T	31730.00	31300.00
Steel Long-MGG (I)	1 T	31800.00	31400.00
Steel Long-Raipur (I)	1 T	28960.00	28460.00
Sugar M Delhi (N)	1 Q	3245.00	3275.00
Sugar M Grade-Kanpur (N)	1 Q	3390.50	3419.05
Sugar M Grade-Kolhap (N)	1 Q	3290.00	3283.75
Sugar M Kolkatta (N)	1 Q	3485.70	3476.20
Sugar M Muzaff (N)	1 Q	3288.00	3293.55
Sugar S-Kolhapur (N)	1 Q	3157.00	3162.00
Turmeric Nizamabad (N)	1 Q	5927.50	5908.35
Wheat Delhi (N)	1 Q	2207.85	2205.00
Wheat Kota (N)	1 Q	2157.25	2166.65
Wheat New Indore (N)	1 Q	2151.25	2180.00
Wheat New Kanpur (N)	1 Q	2130.00	2127.50
Wheat New-Rajkot (N)	1 Q	2185.00	2190.00
Yellow Peas Mum (N)	1 Q	5500.00	5600.00
Yellow Peas-Kanpur (N)	1 Q	5600.00	5550.00
Zinc Mumbai (M)	1 K	178.15	177.35

* as on Feb 03, 20

(M) MCX ,(N) NCDEX & (I) ICEX Spot prices

जिंस वायदा

DAY SESSION

दिवस सत्र (मंगलवार)

कृषि जिंस

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Cotton				
Cotton MCX(1 B)				
Feb 28	19170, 19290, 19110, 19230	3236	502	27313
Mar 31	19430, 19540, 19380, 19510	1713	270	6395
Apr 30	19750, 19800, 19700, 19790	412	55	493
CottonSeed Oil-Akola NCDEX(1 Q)				
Feb 20	1750, 1769, 1728, 1757	36600	2933	45370
Mar 20	1760, 1790, 1747, 1775	39060	3112	66500
Apr 20	1795, 1814, 1775, 1799	6390	573	16340
May 20	1825, 1837, 1805, 1822	880	81	4580
Kapas MCX(20 K)				
Apr 30	1067, 1071, 1063, 1069	656	105	852
Shankar Kapas-Rajkot NCDEX(20 Kg)				
Apr 30	1063, 1071.5, 1062.5, 1069	1193	462	3440
Grains				
Guar Seed 10 NCDEX(1 Qtl)				
Feb 20	3842, 3886, 3832, 3876	20280	1783	44525
Mar 20	3888, 3934, 3880, 3922	26010	2487	47890
Apr 20	3932, 3974, 3932, 3960	1480	155	1350
Oil and Oilseeds				
CastorSeed New-Disa NCDEX(1 Qtl)				
Feb 20	3890, 3890, 3850, 3856	3500	420	12280
Mar 20	3900, 3904, 3860, 3866	4470	575	18835
Apr 20	3922, 3922, 3880, 3900	985	146	4120
Crude Palm Oil MCX(10 K)				
Feb 28	732, 747.9, 725.7, 745.8	30090	2113	45990
Mar 31	727, 740, 720, 738	8660	565	25300
Apr 30	714.1, 732.5, 714.1, 731.3	380	34	2740
Mentha Oil MCX(1 K)				
Feb 28	1189, 1190, 1177.3, 1181	130.32	311	179.64
Mar 31	1173.3, 1189, 1173, 1177	25.92	65	57.96
May 29	1159.9, 1159.9, 1159.9, 1159.9	0.36	1	3.6
Mustard Seed Rape Oil NCDEX(1 Q)				
Feb 20	4091, 4128, 4078, 4107	7470	579	12080
Apr 20	4097, 4108, 4066, 4104	9420	761	15430
May 20	4110, 4130, 4090, 4113	550	40	3820
Ref Soy Oil-IDR-2016 NCDEX(10 Kg)				
Feb 20	841.6, 849.4, 836.4, 846.6	13625	1485	37560
Mar 20	823, 836.2, 819.4, 833.4	18405	1833	47885
Apr 20	818, 830.4, 812.6, 829	1345	183	5465
Soyabean Indore NCDEX(1 Q)				
Feb 20	4076, 4088, 4040, 4062	24885	1883	88340
Mar 20	4062, 4090, 4032, 4064	29525	2313	129400
Apr 20	4066, 4098, 4046, 4072	8485	794	72320
May 20	4066, 4114, 4066, 4092	1190	166	14040
Jun 19	4110, 4110, 4110, 4110	10	2	225
Others				
GuarGum 5T-Jodhpur NCDEX(1 Qtl)				
Feb 20	6850, 6902, 6815, 6884	5665	818	16760
Mar 20	6924, 6989, 6896, 6963	8000	1144	47630
Apr 20	7007, 7080, 7005, 7065	1100	166	1300
Pulses				
Chana-Bikaner NCDEX(1 Qtl)				
Mar 20	4025, 4028, 3965, 3971	12470	954	22360
Apr 20	4020, 4020, 3975, 3981	3900	295	11180
May 20	4022, 4042, 4015, 4020	1530	85	3850
Jun 19	4080, 4080, 4071, 4071	40	4	40
Spices				
Cardamom MCX(1 K)				
Feb 14	3597.7, 3678.6, 3570, 3608.3	0.5	5	4.6
Mar 13	3685.1, 3685.1, 3650, 3668.3	0.3	3	4
Coriander-Kota NCDEX(1 Q)				
Apr 20	6255, 6400, 6252, 6378	3370	249	7720
May 20	6311, 6389, 6306, 6336	260	23	730
Jeera Unjha NCDEX(1 Q)				
Mar 20	13900, 13900, 13710, 13775	717	223	2172
Apr 20	13505, 13565, 13425, 13535	285	92	1650
Turmeric Nizamabad NCDEX(1 Q)				
Mar 20	5896, 6044, 5880, 6018	1185	222	4810
Apr 20	5878, 6010, 5854, 5992	595	112	4395

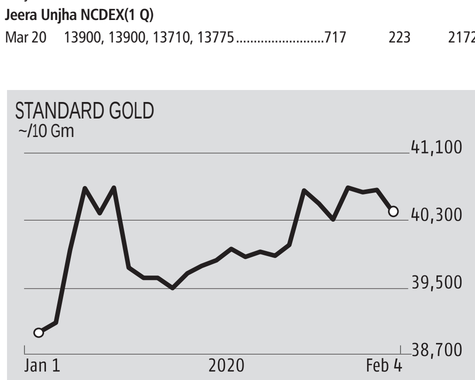

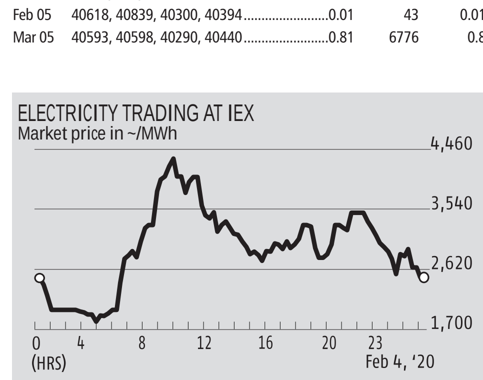

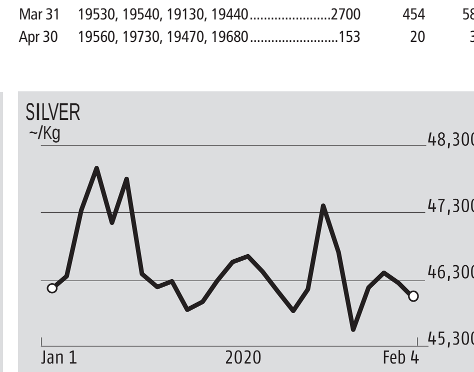

धातु

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Metal- non ferrous				
Aluminium Mini MCX(1 K)				
Feb 28	135.85, 137.15, 134.9, 136.9	8227	5381	5782
Mar 31	137, 137.8, 135.8, 137.65	307	277	482
Apr 30	136.9, 136.9, 136.9, 136.9	1	1	1
Copper MCX(1 K)				
Feb 28	424.7, 429.8, 424.7, 428.8	23650	7520	12237.5
Mar 31	427.85, 430.55, 427.25, 430.15	637.5	249	1110
Lead MCX(1 K)				
May 29	147.05, 147.05, 147.05, 147.05	2	1	7
Lead Mini MCX(1 K)				
Feb 28	145.95, 146.9, 145.1, 146.2	7284	5086	5171
Mar 31	146.65, 147.2, 145.65, 146.65	210	205	526
Apr 30	149.5, 149.5, 145.6, 147.65	3	3	1
Nickel MCX(1 K)				
Feb 28	944, 967.8, 944, 958.9	16374	9800	3417
Mar 31	949, 965.9, 947.7, 956.3	217.5	140	141
Zinc Mini MCX(1 K)				
Feb 28	170.8, 173.1, 170.8, 172.55	33626	18916	18233
Mar 31	172.95, 174, 171.55, 172.85	1000	830	2604
Apr 30	173, 173, 173, 173	6	3	6
Metal- precious				
Gold MCX(10 G)				
Feb 05	40408, 40500, 40370, 40419	0.02	15	0.11
Apr 03	40651, 40689, 40355, 40529	6.88	5783	17.79
Jun 05	40866, 40866, 40538, 40690	0.37	340	4.85
Gold Guinea MCX(8 G)				
Feb 28	32370, 32370, 32200, 32345	0	257	0.01
Mar 31	32265, 32490, 32265, 32335	0	45	0
Gold Mini MCX(10 G)				
Feb 05	40618, 40839, 40300, 40394	0.01	43	0.01
Mar 05	40593, 40598, 40290, 40440	0.81	6776	0.8
Apr 03	40635, 40663, 40351, 40517	0.15	1258	0.27
Gold Petal MCX(1 Gm)				
Feb 28	4021, 4025, 4005, 4012	0	967	0.01
Mar 31	4037, 4040, 4025, 4032	0	212	0
Apr 30	4078, 4078, 3959, 3985	0	7	0
Silver MCX(1 K)				
Mar 05	46367, 46367, 45836, 46139	282.87	7856	274.83
May 05	46583, 46753, 46378, 46675	4.86	144	20.64
Silver Micro MCX(1 K)				
Feb 28	46047, 46200, 45851, 46143	32.88	24303	28.55
Apr 30	46688, 46750, 46420, 46690	3.03	2113	6.39
Jun 30	47100, 47100, 47000, 47052	0.01	10	0.15
Silver Mini MCX(1 K)				
Feb 28	46024, 46346, 45845, 46166	111.72	17609	48.53
Apr 30	46641, 46777, 46412, 46693	3.84	701	6.58

तेल एवं गैस

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Gas				
Natural Gas MCX(1 MB)				
Feb 25	130.6, 131.7, 129.4, 131.1	51851mb	23431	53966mb
Mar 26	134.1, 134.9, 133.1, 134.6	1513mb	983	4715mb
Apr 27	138.7, 139.4, 137.8, 139.1	149mb	91	183mb
Oil				
Crude Oil MCX(1 BL)				
Feb 19	3606, 3658, 3593, 3630	18391bl	106431	3953bl
Mar 19	3632, 3682, 3621, 3657	473bl	3805	328bl
Apr 20	3662, 3700, 3657, 3673	1bl	9	4bl

सायं सत्र (सोमवार)

कृषि जिंस

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Cotton				
Cotton MCX(1 B)				
Feb 28	19280, 19290, 18840, 19180	9906	1485	27083
Mar 31	19530, 19540, 19130, 19440	2700	454	5897
Apr 30	19560, 19730, 19470, 19680	153	20	310
Kapas MCX(20 K)				
Apr 30	1071.5, 1071.5, 1059.5, 1062	840	102	920
Shankar Kapas-Rajkot NCDEX(20 Kg)				
Apr 30	1065, 1072, 1060, 1063.5	2606	1326	3314
Oil and Oilseeds				
Crude Palm Oil MCX(10 K)				
Feb 28	744, 746.9, 722.6, 727.9	34670	2386	47540
Mar 31	737, 737.5, 715.7, 720.6	10200	579	23040
Apr 30	727, 727, 710.4, 713.2	300	26	2820
Ref Soy Oil-IDR-2016 NCDEX(10 Kg)				
Feb 20	843.2, 848.4, 833.4, 836.8	27100	2932	40170
Mar 20	827, 833, 817, 820.6	23465	2526	49565
Apr 20	824, 826.6, 810, 812.6	2285	315	5530
May 20	-, 821.2, -, 821.2	5	1	115

धातु

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Metal- non ferrous				
Aluminium Mini MCX(1 K)				
Feb 28	139, 139.05, 134.7, 135.8	12612	7771	5039
Mar 31	139.45, 139.45, 135.8, 136.75	525	451	478
Apr 30	138.95, 138.95, 136, 137.8	6	6	2
Copper MCX(1 K)				
Feb 28	427.7, 430.2, 420.6, 421.75	36327.5	11968	13950
Mar 31	431.3, 431.3, 423.05, 424.05	670	262	1055
Lead Mini MCX(1 K)				
Feb 28	147.6, 148.1, 144.5, 144.8	14076	9203	4939
Mar 31	148.2, 148.45, 145.2, 145.45	542	489	481
Nickel MCX(1 K)				
Feb 28	947, 950.8, 934.3, 937.8	18888	11429	2214
Mar 31	943.4, 947.8, 933.4, 936.6	177	115	120
Zinc MCX(1 K)				
May 29	178.2, 178.2, 172.4, 173.8	13	13	18
Zinc Mini MCX(1 K)				
Feb 28	174.6, 176, 170.15, 170.35	50779	29752	18147
Mar 31	175.55, 176.1, 170.8, 171	2068	1480	2390
Apr 30	175, 175, 172, 173.55	3	3	1
Metal- precious				
Gold MCX(10 G)				
Feb 05	41011, 41050, 40371, 40661	0.09	76	0.24
Apr 03	41079, 41140, 40582, 40744	13.17	11045	17.91
Jun 05	41296, 41302, 40748, 40938	0.96	845	4.65
Gold Guinea MCX(8 G)				
Feb 28	32500, 32519, 32306, 32346	0.01	717	0.01
Mar 31	32620, 32620, 32165, 32395	0	107	0
Gold Mini MCX(10 G)				
Feb 05	41178, 41178, 40590, 40633	0.02	116	0.06
Mar 05	40868, 40995, 40512, 40626	1.74	13870	0.77
Apr 03	41063, 41091, 40583, 40716	0.28	2285	0.27
Gold Petal MCX(1 Gm)				
Feb 28	4050, 4050, 4017, 4023	0.01	1991	0.01
Mar 31	4065, 4065, 4035, 4044	0	429	0
Silver MCX(1 K)				
Mar 05	46669, 46690, 45755, 45890	658.98	18536	257.13
May 05	47150, 47195, 46340, 46483	10.23	327	19.17
Silver Micro MCX(1 K)				
Feb 28	47050, 47050, 45784, 45900	93.42	65358	26.01
Apr 30	47405, 47405, 46356, 46495	10.91	7756	5.82
Jun 30	47600, 47620, 46900, 46991	0.05	43	0.15
Silver Mini MCX(1 K)				
Feb 28	47000, 47000, 45786, 45908	252.4	40032	41.5
Apr 30	47203, 47213, 46350, 46501	10.69	1885	6.33

तेल एवं गैस

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Gas				
Natural Gas MCX(1 MB)				
Feb 25	134, 135.1, 130.2, 131.1	154404mb	72329	48649mb
Mar 26	137.8, 138.6, 134.2, 134.8	5226mb	3423	4459mb
Apr 27	139.7, 142.8, 138.8, 139.5	153mb	118	164mb
Oil				
Crude Oil MCX(1 BL)				
Feb 19	3690, 3724, 3572, 3626	54990bl	314655	2903bl
Mar 19	3689, 3744, 3601, 3651	1668bl	13722	311bl
Apr 20	3731, 3755, 3679, 3721	1bl	6	3bl

g-grams, k-kilograms, q-quintals, t-tonnes, b-bales,bl-barels,mb-mmBTU,m-Mnd; Quantity & Open interest in tonnes except for crude oil and natural gas; For Gas is '000 mmBTU & for crudeoil in '000 barrel; Market price in ₹.

कोरोनावायरस 25 और देशों में फैला

चीन में जानलेवा वायरस के संक्रमण से मृतकों की तादाद 427 पहुंची, फिलीपींस-हॉन्गकॉन्ग में 2 की मौत

हॉन्गकॉन्ग में मंगलवार को कोरोनावायरस से संक्रमित एक व्यक्ति की मौत हो गई। चीन से फैली इस महामारी से अब तक 427 लोगों की मौत हो चुकी है और चीन से बाहर इस वायरस के संक्रमण से हुई यह दूसरी मौत है। चीन में संक्रमित लोगों की तादाद में 3,235 का इजाफा हुआ और कुल तादाद 20, 438 हो गई। इसके अलावा 25 अन्य देशों और चीन के विशेष प्रशासन वाले क्षेत्रों हॉन्गकॉन्ग और मकाऊ क्षेत्र में संक्रमण के करीब 200 मामले दर्ज किए गए हैं। इस वायरस का संक्रमण दुनिया भर में फैल चुका है और इससे वैश्विक आर्थिक वृद्धि पर भी खतरा मंडरा रहा है। एक दिन पहले शांघाई बेंचमार्क सूचकांक के 400 अरब डॉलर बाजार मूल्य में कमी आने की चिंता के बाद चीन का बाजार आज कमोबेश स्थिर नजर आया और पिछले हफ्ते की बिकवाली के बाद वैश्विक बाजार ने भी वापसी की। हालांकि बुरी खबर का आना जारी है।

दुनिया के सबसे बड़े जुआ केंद्र मकाऊ में सभी कैसिनो संचालकों को दो हफ्ते के लिए कैसिनो बंद करने के लिए कहा गया है ताकि वायरस के प्रसार को रोकने में मदद मिले। हुंडई मोटर ने कहा है कि यह धीरे-धीरे दक्षिण कोरिया की फैक्टरियों में उत्पादन बंद करेगी क्योंकि वायरस के प्रकोप से आपूर्ति में मुश्किल आ रही है। हॉन्गकॉन्ग की मौत के बाद कोरोनावायरस से मरने वालों की तादाद 427 हो गई है जिसमें फिलीपींस में पिछले हफ्ते मरने वाला एक व्यक्ति भी शामिल है जो वायरस के चीन के वुहान शहर से वापस लौटा था। सिंगापुर में संक्रमण के छह अन्य मामले भी दर्ज किए गए हैं जिसमें चार स्थानीय संक्रमण का मामला है। वहां के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि संक्रमण की कुल तादाद बढ़कर 24 हो गई है। इसके अलावा अमेरिका में भी संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं जिनमें कैलिफॉर्निया का एक मरीज शामिल है जो अपने घर में एक व्यक्ति के संपर्क से संक्रमित हुआ है जो चीन से ही संक्रमित होकर आया था। अमेरिका के इलिनॉय में पिछले हफ्ते व्यक्ति से व्यक्ति के संपर्क से संक्रमण का मामला सामने आया था जिसके बाद यह दूसरा ऐसा मामला है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस फ्लू जैसे वायरस के प्रसार को वैश्विक आपातकाल घोषित कर दिया है और विशेषज्ञों का कहना है कि अब भी इस वायरस की किस्म की जानकारी नहीं है जिसमें इससे होने वाली मृत्यु दर और संक्रमण का जरिया भी शामिल है। इस वायरस की अनिश्चितता को देखते हुए ही कुछ देश ज्यादा सतर्कता बरत रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने चीन के हुबेई प्रांत के शहर वुहान से सैकड़ों नागरिकों को निकालकर हिंद महासागर के एक द्वीप पर भेजा है जबकि जापान ने 3,700 से अधिक यात्रियों वाले जहाज को जापान के बंदरगाह योकोहामा में अलग रखकर यात्रियों की जांच शुरू कर दी है। दरअसल इस जहाज में यात्रा करने वाले हॉन्गकॉन्ग के एक यात्री की कोरोनावायरस जांच सकारात्मक थी।

दक्षिण कोरिया के सोल में विदेशी मुद्रा कारोबारी (फोटोः पीटीआई)

बढ़ती महामारी

- चीन से बाहर लगभग दो दर्जन जगहों पर 200 से अधिक लोग वायरस से संक्रमित पाए गए हैं
- चीन में वायरस से संक्रमित लोगों की तादाद बढ़कर 20,438 हुई
- हाल की गिरावट के बाद मंगलवार को शांघाई, हॉन्गकॉन्ग और सियोल के बाजार बढ़त के रुझान के साथ खुले

हड़ताल जारी

हॉन्गकॉन्ग में सैकड़ों चिकित्साकर्मियों ने कोरोनावायरस को फैलने से रोकने के लिए चीन के साथ लगने वाली सीमाओं को बंद करने की मांग को लेकर सोमवार को काम ठप कर दिया था। यह हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। एक 26 वर्षीय नर्स का कहना था कि वे सरकार को धमकी नहीं दे रहे हैं बल्कि वे महामारी को रोकना चाहते हैं। एशिया के इस वित्तीय केंद्र में कोरोनावायरस के 17 मामले की पुष्टि हो चुकी है और इसके सरकारी अस्पताल मरीजों की बढ़ती तादाद को सेवाएं देने और महामारी को रोकने के उपाय करने की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। हॉन्गकॉन्ग में सार्स का असर देखा गया था जब यह वर्ष 2002 में चीन से फैला था और दुनिया भर में लगभग 800 लोगों की मौत हो गई थी। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक सार्स से उस वक्त हॉन्गकॉन्ग में 299 लोगों की मौत हो गई थी। चीन के आंकड़ों के मुताबिक नया वायरस सार्स के मुकाबले ज्यादा संक्रामक है लेकिन यह अपेक्षाकृत कम घातक है। हालांकि इसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण फैलता है।

अस्पताल का इंतजाम

वुहान में अधिकारियों ने जिम्नेजियम, प्रदर्शनी केंद्रों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के स्थलों को अस्थायी अस्पताल में बदल दिया है जहां कम संक्रमित मरीजों के लिए 3,400 बेड का इंतजाम किया गया है। अमेरिका ने शुक्रवार को ही कहा था वह पिछले 14 दिनों में चीन की यात्रा करने वाले सभी विदेशी नागरिकों पर प्रतिबंध लगाएगा। ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, वियतनाम और अन्य देशों ने भी समान प्रतिबंध लगाए। चीन ने सोमवार को अमेरिका से कहा कि अगर वह महामारी रोकने में कोई मदद करता है तो उसका स्वागत किया जाएगा। व्हाइट हाउस ने कहा कि चीन ने अमेरिका की पेशकश स्वीकार ली है। कई विमानन कंपनियों ने चीन में अपनी विमान सेवाएं देनी बंद कर दी है। हाल में जापान की बड़ी विमानन कंपनी एएनए होल्डिंग्स ने घोषणा की है कि पेइचिंग जाने वाले विमानों की उड़ान में कम से कम सात हफ्ते तक दो-तिहाई कटौती की जाएगी। सिंगापुर एयरशो के आयोजकों का कहना है कि करीब 300 अंतरराष्ट्रीय विमानन अधिकारियों की एक बैठक रद्द कर दी गई है। *एजेंसियां*

वैध वीजा रद्द

भारत ने चीनी नागरिकों और पिछले दो हफ्तों में चीन गए विदेशी नागरिकों के मौजूदा वीजा को रद्द कर वीजा नियमों को मंगलवार को और सख्त कर दिया। चीन के वुहान शहर में कोरोनावायरस की वजह से 2 फरवरी को भारत ने चीनी यात्रियों और चीन में रह रहे विदेशी नागरिकों के लिए ई-वीजा पर अस्थायी रोक लगा दी। केरल में इसके तीन मामले सामने आए हैं। इस बीच घरेलू वाहन निर्माता कंपनियों के संगठन सायम ने बताया है कि ऑटो एक्सपो में भाग ले रही चीनी कंपनियों ने पुष्टि की है कि प्रदर्शनी के दौरान लगने वाले उनके स्टॉल कंपनी के भारतीय कर्मचारी ही संभालेंगे।

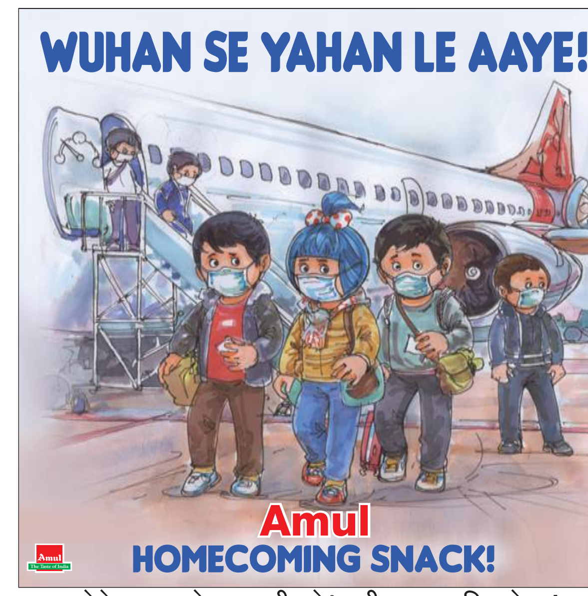

कोरोनावायरस के कारण चीन से भारतीय बचाकर निकाले गए!

विरोध करने पर मरीज की गिरफ्तारी के निर्देश

राजीव भास्कर

कोरोनावायरस का एक संदिग्ध मामला पंजाब के फरीदकोट में सामने आया है। संदिग्ध मरीज को गुरु गोविंद सिंह मेडिकल कॉलेज ऐंड हास्पिटल, फरीदकोट में अलग वॉर्ड में भर्ती कराया गया है। वह चीन के रास्ते कनाडा से भारत आया है। उसकी फ्लाइट शांघाई में नौ घंटे के लिए रुकी थी। 38 वर्षीय यह व्यक्ति फरीदकोट जिले के कोटकापुरा शहर का है। बताया जाता है कि उस मरीज ने फरीदकोट में सिविल सर्जन से सोमवार को सांस संबंधी कुछ दिक्कतों की शिकायत की थी। सिविल सर्जन ने उसका सैंपल लिया और उसे जांच के लिए पुणे स्थित प्रयोगशाला भेज दिया है।

संदिग्ध ने अलग वॉर्ड में रहने से इनकार कर दिया था, तब स्वास्थ्य अधिकारियों ने इसकी जानकारी जिलाधिकारी को दी। जिलाधिकारी ने एसएसपी फरीदकोट को पत्र लिखकर संबंधित पुलिस अधिकारियों को स्वास्थ्य अधिकारियों की मदद करने की गुहार लगाई है ताकि संदिग्ध को अलग रखा जा सके।

हुबेई में मुर्गीपालकों की बढ़ रही हैं मुश्किलें

रॉयटर्स

- परिवहन पर प्रतिबंधों से हुबेई प्रांत के मुर्गीपालकों को हो रहा है नुकसान
- किसानों को अपने पक्षियों को मारने के लिए किया जा रहा है मजबूर
- चीन में हुबेई मुर्गी-अंडों का प्रमुख उत्पादक प्रांत है

चीन में कोरोनावायरस महामारी का केंद्र बने हुबेई प्रांत के मुर्गी एवं अन्य पक्षीपालक वायरस के प्रकोप के बाद अपने पक्षियों को मार रहे हैं। यहां के किसान वायरस को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए नए नियमों के तहत ही इन पक्षियों को मार रहे हैं। इस बीमारी के फैलने के बाद से जीवित जानवर के परिवहन, चारा आपूर्ति और बूचड़खानों पर रोक लग गई है।

हुबेई पोल्ट्री एसोसिएशन के एक अधिकारी के मुताबिक कुछ मुर्गी पालकों ने अपने मुर्गियों का खाना आधा कर दिया है क्योंकि उनके पास चारे का अभाव है जबकि अन्य किसानों ने पक्षियों को मार दिया है। इस पोल्ट्री संगठन ने पिछले हफ्ते सरकार से चारे की आपूर्ति तुरंत बहाल करने की अपील की थी। अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, 'वयस्क हो चुके पक्षियों को सुरक्षित तरीके से मारा गया है।' हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि कितने जानवरों को और कैसे मारा गया है। जीवित मुर्गियों के परिवहन पर प्रतिबंध होने से हुबेई में मुर्गीपालक बाजार में मुर्गे का मांस और अंडे नहीं भेज पा रहे हैं।

पोल्ट्री को इस वायरस के संक्रमण का संभावित कारक माना जा रहा है। हुबेई प्रांत के वुहान शहर में ही कोरोनावायरस की सबसे पहले पहचान की गई थी।

यहां के हुआंगगांग शहर के पास एक महिला किसान प्रतिदिन करीब 7,000 अंडों का उत्पादन करती है। उनका कहना है कि मुर्गीपालकों के पास इस मुश्किल से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। वह कहती है, 'मैं अपने भंडारित चारे का इस्तेमाल कर रही हूं लेकिन मुझे नहीं पता कि अंडों का क्या करूंगी।' चीन की सोशल मीडिया पर इस हफ्ते वायरल हुए वीडियो में नजर आ रहा है कि किसान अनजान जगहों पर चूजों, बत्तख के बच्चों और वयस्क बत्तखों को जीवित ही दफना रहे हैं। इसके साथ ही वे अंडे भी दफन कर रहे हैं। रॉयटर्स उस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं कर सका और न ही उसके समय और स्थान की तस्दीक करती है।

चीन ने 2019 में 2.2 करोड़ टन पोल्ट्री मांस का उत्पादन किया था जो इससे एक वर्ष पहले के मुकाबले 12 फीसदी अधिक था। इस बीच अफ्रीकी स्वाइन फ्लू के कारण सुअर के मांस की कमी रही। हुबेई में हर साल करीब 50 करोड़ पक्षियों को मारा जाता है और यह एक प्रमुख अंडा उत्पादक प्रांत है।

विश्लेषकों के मुताबिक इसके बाहर के प्रांत भी प्रभावित हुए हैं। ऐसे में चीन के कई शहरों ने भी कोरोनावायरस को नियंत्रित करने की कोशिश के तहत सड़कों पर अवरोधक खड़ा किया है ताकि बाहरी प्रवेश न हो। इस बीमारी के प्रसार के कारण एक दिन के चूजों और बत्तख के बच्चों को किसानों को बेचने वाले हैचरीज को विशेष तौर पर धक्का लगा है। किसान यहां से चूजों की खरीदारी कर उन्हें पालते है जिसे बाद में बूचड़खानों में भेजा जाता है।

प्रजनन वाले बत्तखों की चीन की दूसरी सबसे बड़ी आपूर्तिकर्ता कंपनी फ्रांस की ओरविया के चीन में महाप्रबंधक डोंग जिआओबो ने कहा, 'परिवहन पर कठोर पाबंदी होने से मुर्गीपालक अपने फार्म में इनकी उपलब्धता के लिए नए चूजों को खरीदने में या तो सक्षम नहीं हो पा रहे हैं या फिर वे इसके लिए इच्छुक नहीं हैं।'

उन्होंने कहा, 'बत्तख के प्रति चूजे की कीमत 5 सेंट के निचले स्तर पर आ गई है। किसी को नहीं पता कि उसके उत्पादन का क्या होगा।'

रेबोबैंक के वरिष्ठ विश्लेषक पान चेनजुन ने कहा, 'बहुत सारे बूचड़खाने पर्याप्त श्रमिक उपलब्ध नहीं होने के कारण कम क्षमता पर भी परिचालित हो रहे हैं।'